वर्ष: 5 अंक: 14

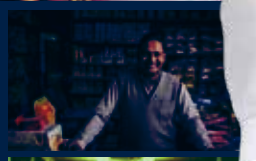
16-31 जनवरी, 2025 (निःशुल्क)

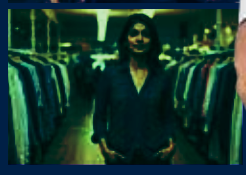
न्यू इंडिया समाचार













स्टार्टअप

युवा सामर्थ्य की पहचान

नई पीढ़ी के लिए आकर्षण और आत्मविश्वास का केंद्र बनी स्टार्टअप पहल की सफलताओं ने दुनिया में दी भारत के युवा सामर्थ्य को नई पहचान

संविधान हमारा मार्गदर्शक, समय की हर कसौटी पर उतरा खरा



साल 2014 से शुरू हुए 'मन की बात' का कार्यक्रम देश की सामूहिक शक्ति का एक जीवंत दस्तावेज बन गया है। लोगों ने इस कार्यक्रम को अपना बनाया है। श्रोताओं ने हर महीने अपने विचार और प्रयास साझा किए हैं। इस दौरान कभी यंग इनोवेटर के आइडिया तो कभी किसी बेटी की उपलब्धि ने देश को गौरवान्वित किया। एक तरह से यह कार्यक्रम पॉजिटिव एनर्जी के विस्तार का मंच बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' के 117वें एपिसोड में भारतीय संविधान, प्रयागराज महाकुम्भ सहित कई मुद्दों पर बात की। प्रस्तुत है 'मन की बात' के अंश...

- **कसौटी पर खरा संविधान :** 26 जनवरी 2025 को संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सभी के लिए यह गौरव की बात है। संविधान निर्माताओं ने जो संविधान सौंपा है वह समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। संविधान हमारे लिए guiding light है, मार्गदर्शक है। यह भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से मैं आज यहां हूं, आपसे बात कर पा रहा हूं।

- **constitution75.com :** वर्ष 2024 में 26 नवंबर को संविधान दिवस से एक साल तक चलने वाली कई एक्टिविटी शुरू हुई हैं। देश के नागरिकों को संविधान की विरासत से जोड़ने के लिए constitution75.com नाम से एक खास वेबसाइट बनाई गई है। इसमें संविधान की प्रस्तावना पढ़कर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अलग-अलग भाषाओं में संविधान पढ़ सकते हैं, संविधान के बारे में प्रश्न भी पूछ सकते हैं।

- **प्रयागराज में महाकुम्भ :** प्रयागराज में महाकुम्भ हो रहा है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए महाकुम्भ एकता का भी महाकुम्भ होता है। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा... महाकुम्भ का संदेश, एक हो पूरा देश और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा... गंगा की अविरल धारा, न बंटे समाज हमारा।

- **एक भारत-श्रेष्ठ भारत :** एनिमेशन, फिल्में, टीवी धारावाहिक की लोकप्रियता दिखाती है कि भारत की क्रिएटिविटी इंडस्ट्री में कितनी क्षमता है। यह इंडस्ट्री न सिर्फ देश की प्रगति में बड़ा योगदान दे रही है बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। मैं फिल्म और मनोरंजन जगत को इसलिए भी बधाई देता हूं क्योंकि उसने 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के भाव को सशक्त किया है।

- **फिल्म जगत की महान हस्तियां :** वर्ष 2024 में हम फिल्म जगत की कई महान हस्तियों की 100वीं जयंती मना रहे हैं। इन विभूतियों ने भारतीय सिनेमा को विश्व-स्तर पर पहचान दिलाई। राज कपूर जी ने फिल्मों के माध्यम से दुनिया को भारत की सॉफ्ट पावर से परिचित कराया। रफी साहब की आवाज में वो जादू था जो हर दिल को छू लेता था। अक्किनेनी नागेश्वर राव गारू ने तेलुगु सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तपन सिन्हा जी की फिल्मों ने समाज को एक नई दृष्टि दी।

- **कैंसर से लड़ाई :** दुनिया के मशहूर मेडिकल जर्नल लांसेट की स्टडी वाकई बहुत उम्मीद बढ़ाने वाली है। इस जर्नल के मुताबिक अब भारत में 30 दिनों के भीतर कैंसर का इलाज शुरू हो जा रहा है। 'आयुष्मान भारत योजना' ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योजना की वजह से कैंसर के 90 प्रतिशत मरीज समय पर अपना इलाज शुरू करा पाए हैं।

- **सब्जी क्रांति :** कालाहांडी का गोलामुंडा ब्लॉक एक वेजिटेबल हब बन गया है। इसकी शुरुआत सिर्फ 10 किसानों के एक छोटे से समूह से हुई। इस समूह ने मिलकर एक FPO - 'किसान उत्पाद संघ' की स्थापना की। कालाहांडी की यह सफलता हमें सिखाती है कि संकल्प शक्ति और सामूहिक प्रयास से क्या नहीं किया जा सकता।

*'मन की बात' पूरी सुनने के लिए **QR** कोड स्कैन करें।*

न्यू इंडिया
समाचार

वर्ष: 5, अंक: 14 | 16-31 जनवरी, 2025

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र ओझा
प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

मुख्य सलाहकार संपादक
संतोष कुमार

सलाहकार संपादक
विभोर शर्मा

वरिष्ठ सहायक सलाहकार संपादक
पवन कुमार

सहायक सलाहकार संपादक
अखिलेश कुमार
चन्दन कुमार चौधरी

भाषा संपादन
सुमित कुमार (अंग्रेजी)
रजनीश मिश्रा (अंग्रेजी)
नदीम अहमद (उर्दू)

चीफ डिजाइनर
श्याम तिवारी

सीनियर डिजाइनर
फूलचंद तिवारी

डिजाइनर
अभय गुप्ता
सत्यम सिंह



13 भाषाओं में उपलब्ध न्यू इंडिया समाचार को पढ़ने के लिए क्लिक करें।

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

न्यू इंडिया समाचार के पुराने अंक पढ़ने के लिए क्लिक करें

https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx

न्यू इंडिया समाचार के बारे में लगातार अपडेट के लिए फॉलो करें: @NISPIBIndia

अंदर के पन्नों पर...

आवरण कथा

9 वर्ष स्टार्टअप इंडिया के

स्टार्टअप हब
बनता नया भारत

वर्ष 2014 में जब देश का मिजाज बदला तो पहली बार कई नए शब्द सुनने में आए! स्टार्टअप एक ऐसा ही शब्द है। इनोवेशन और इंक्यूबेशन के रास्ते युवा सपनों की तकदीर बदलने में विश्वास करने वाली केंद्र सरकार के प्रयासों की बदौलत डेढ़ लाख से अधिक स्टार्टअप के साथ भारत अब इस मामले में दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत व्यवस्था है... | 18-33



अटलजी की 100वीं जयंती

राष्ट्र निर्माण के 'अटल' आदर्श की शताब्दी



भारत के राष्ट्रपुरुष के रूप में अटलजी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी लेखनी की जरिए याद किया | 10-12

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि

भारत के आर्थिक उदारीकरण के वास्तुकार



पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए विद्वान अर्थशास्त्री और सुधारों के लिए समर्पित नेता के रूप में किया याद | 14-15

समाचार सार | 4-5

भारतीय गणतंत्र के 75 वर्ष
भारतीयता का उत्सव | 6-9

व्यक्तित्व - डॉ. बालकृष्ण विट्ठलदास दोशी
वास्तुकला की दुनिया का ध्रुवतारा | 13

27 जनवरी : बोडो समझौते की छठी वर्षगांठ
शांति समझौते के बाद बोडोलैंड में विकास की नई लहर | 16-17

केन-बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना
बुंदेलखंड क्षेत्र में खुशहाली और समृद्धि की नई राह | 34-36

प्रेम, सद्भाव व भाईचारे का मार्ग बताती हैं प्रभु ईसा मसीह की शिक्षाएं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस समारोह में हुए शामिल | 37

राजस्थान की चमक और विकास का उत्सव
पीएम मोदी ने 46,300 करोड़ रु. की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन | 38-39

डिजिटलाइजेशन से पारदर्शी पैक्स
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एम-पैक्स की शुरुआत की | 40-41

रोजगार मेला : देश छू रहा नई ऊंचाइयां, नए अवसरों का हो रहा निर्माण
रोजगार मेले में पीएम मोदी ने 71,000 से अधिक युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र | 42-43

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की एक दशक में ऊंची उड़ान
जीवन को ऊंचाई देने में बेटी-बेटे बनें सपने के दो पंख | 44-46

भारत और कुवैत... रिश्तों को नई उड़ान
कुवैत में पीएम मोदी का दो दिवसीय दौरा देगा रिश्तों को नई पहचान | 47-49

भारत-श्रीलंका संबंध : साझा भविष्य के लिए साझेदारी को बढ़ावा
श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायक की भारत यात्रा | 50-51

किसानों को समर्पित 2025 की केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक
फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ा, डीएपी के लिए विशेष पैकेज | 52

प्रकाशक और मुद्रक: योगेश कुमार बवेजा, महानिदेशक, सीबीसी (केंद्रीय संचार ब्यूरो)। **मुद्रण:** जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा. लि., बी-278, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020। **पत्राचार और ईमेल के लिए पता:** कमरा संख्या-316, नेशनल मीडिया सेंटर, रायसिना रोड, नई दिल्ली- 110001। **ईमेल-** response-nis@pib.gov.in आर. एन. आई. नंबर DELHIN/2020/78812

संपादक की कलम से...

एक दशक में ही स्टार्टअप पहल बनी देश की कार्य संस्कृति

सादर नमस्कार।

21वीं सदी में देश को आगे बढ़ाने में देश की युवा शक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे आगे रखा है, इसलिए उन्होंने युवा शक्ति को अमृत पीढ़ी का नाम दिया है। इस पीढ़ी को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से स्टार्टअप की पहल को नए आयाम दिए हैं। उनकी इस सोच के साथ शुरू हुई स्टार्टअप पहल बीते एक दशक में नई क्रांति का द्योतक बन गया है। आज भारत दुनिया के तीन शीर्ष स्टार्टअप ईको-सिस्टम में शामिल है। स्टार्टअप की यही भावना नए भारत को बाकी दुनिया से अलग करती है। आज लाखों युवा नए स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के साथ भारत की प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं।

2014 के पहले तक देश में कुछ गिने-चुने स्टार्टअप थे और यह शब्द लोगों को सुनने को भी नहीं मिलता था लेकिन आज डेढ़ लाख से अधिक स्टार्टअप और 118 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ भारत इस दिशा में नई गाथा लिख रहा है। स्टार्टअप शुरू से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में रहा है। यही कारण है कि भारत की अध्यक्षता वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में भारतीय स्टार्टअप को अंतरराष्ट्रीय मंच देने के लिए एक सहभागी समूह स्टार्टअप-20 गठित किया गया। स्टार्टअप की राह आसान करने के लिए सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। हैकाथॉन और चैलेंज का आयोजन, इनसेंटिव देने, ट्रेड मार्क और पेटेंट रजिस्ट्रेशन में सहायता सहित कई सुधारों पर लगातार काम जारी है।

अंतरिक्ष क्षेत्र में मैपिंग और ड्रोन क्षेत्र में सुधार किए गए हैं जिससे अनेक क्षेत्रों में अवसर खुले हैं। इसी का परिणाम है कि आज नौजवान अपने पारिवारिक परंपराओं से हट कर कहता है मैं तो स्टार्टअप करूंगा। आज छोटे-छोटे शहरों में भी स्टार्टअप संस्कृति का विस्तार हो रहा है। दुनिया में स्टार्टअप का हब बन रहे भारत की सफलता की कहानी ही हमारी इस बार के अंक की आवरण कथा बनी है।

इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में बालकृष्ण दोशी, पीएम मोदी का पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर कृतज्ञ राष्ट्र का नमन, 22 जनवरी को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पहल के एक दशक पूरे होने और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विशेष सामग्री को इसमें शामिल किया गया है।

साथ ही, रोजगार मेला, केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला, राजस्थान सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर आयोजित एक वर्ष-परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम सहित पखवाड़े भर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अन्य कार्यक्रमों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा, इनसाइड में मन की बात और बैक कवर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 'पराक्रम दिवस' पर विन्रम श्रद्धांजलि इस अंक की विशेषता है।

धीरेन्द्र

(धीरेन्द्र ओझा)

हिंदी, अंग्रेजी व अन्य 11 भाषाओं में उपलब्ध पत्रिका पढ़ें/डाउनलोड करें।
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

आपकी बात...



अच्छी लगी न्यू इंडिया समाचार पत्रिका

मुझे पहली बार न्यू इंडिया समाचार पत्रिका पढ़ने को मिली। यह पत्रिका मुझे अच्छी लगी। मैं न्यू इंडिया समाचार पत्रिका को शुभकामनाएं देता हूं। समय-समय पर हमारे देश के लिए बहुत से नेता और प्रधानमंत्रियों ने योगदान दिया है लेकिन यह पहली बार है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इच्छाशक्ति का उदाहरण दुनिया के सामने पेश किया है।

भास्कर भट्टाचार्य
b_bhatt2@yahoo.com

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका सभी वर्ग व समाज के लिए उपयोगी

वैश्विक एवं भारतीय स्तर पर स्थापित गतिमानों की सुंदर संदर्शिनी की आपकी पहल न्यू इंडिया समाचार पत्रिका की प्रति प्राप्त होना, भारतीय भावनाओं के प्रति गौरान्वित क्षण की प्रदाता है। पत्रिका की सुंदरतम् छवि मन को उत्साहित करते हुए भारतीय परिवेश की जमीनी उपलब्धियों में सार्थकता की परिचायक है। यह पत्रिका सभी वर्ग व समाज के लिए उपयोगी है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि न्यू इंडिया समाचार पत्रिका की प्रति हमें प्रेषित किए जाने की निरंतरता को बनाए रखने की कृपा करें।

दीपेंद्र कुमार शर्मा
jagshantidoot@gmail.com

छात्रों के लिए काफी उपयोगी न्यू इंडिया समाचार पत्रिका

मैंने आपकी पत्रिका- 'न्यू इंडिया समाचार' ऑनलाइन देखी। भारत के नागरिक और हाईस्कूल में पढ़ने वाले छात्र के रूप में, मुझे यह पत्रिका काफी अच्छी और उपयोगी लगी। मैं बदलाव लाने की आकांक्षा रखता हूं और इसकी शुरुआत खुद से होनी चाहिए।

एस.अर्चिता
sanapalaarchita14@gmail.com

नियमित पढ़ना पसंद है न्यू इंडिया समाचार पत्रिका

मैं जाधव मनोहर महादेव, वर्ष 2006 में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त, ग्राम मालोली, तहसील मालशिरस, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र का निवासी हूं। मुझे नियमित रूप से न्यू इंडिया समाचार पत्रिका पढ़ना पसंद है। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है।

जाधव मनोहर महादेव
jadhavmanoharm@gmail.com

पाठकों को सबसे ज्यादा सामग्री प्रदान करती है न्यू इंडिया समाचार पत्रिका

न्यू इंडिया समाचार पाक्षिक पत्रिका पाठकों को सबसे ज्यादा सामग्री प्रदान करती है। पत्रिका में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विविध विचार, समाज, संविधान, साहित्य, संस्कृति, राजनीति और सरकारी योजनाओं को आसान भाषा में पाठकों को बताया जाता है।

एमबी नरसिम्हालु वदावती
mbnarasimhalu@gmail.com

ज्ञान वृद्धि में लाभकारी न्यू इंडिया समाचार

मैं रितिक जैन मध्य प्रदेश के सागर जिले का निवासी हूं। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य है और मैं एक छात्र हूं। आपके द्वारा प्रकाशित पत्रिका न्यू इंडिया समाचार मेरी ज्ञान वृद्धि के लिए अत्यंत लाभकारी है।

रितिक जैन
ritikjain7898@gmail.com

पत्राचार और ईमेल के लिए पता: कमरा संख्या-316,
नेशनल मीडिया सेंटर, रायसिना रोड, नई दिल्ली- 110001
ईमेल- response-nis@pib.gov.in

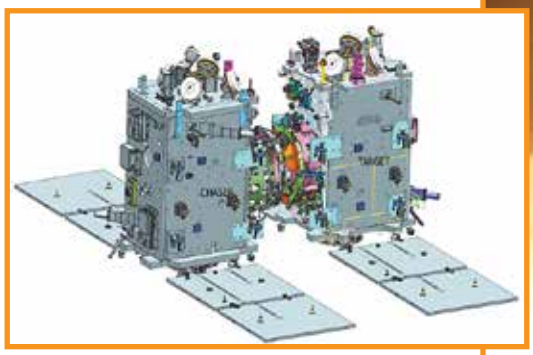
न्यू इंडिया समाचार को आकाशवाणी पर सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें।

अंतरिक्ष में इसरो ने रचा इतिहास

भारत ने की स्पैडेक्स की सफल लॉन्चिंग



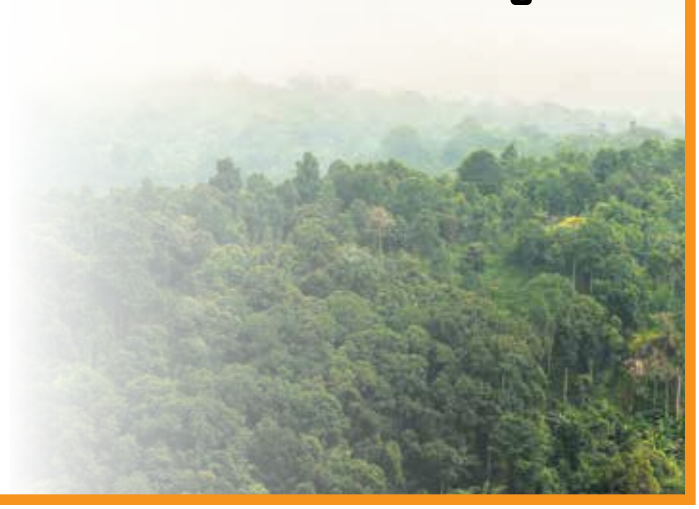
इसरो (**ISRO**) ने 30 दिसंबर को 'स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट' यानी स्पैडेक्स स्पेसक्राफ्ट की सफल लांचिंग कर नया इतिहास रच दिया। यह पीएसएलवी-सी60 रॉकेट से लॉन्च किया गया। यह एक बड़ी सफलता है क्योंकि यह अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक में भारत के लिए एक नया रास्ता खोलती है और अंतरिक्ष में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में उसकी भूमिका को मजबूत करती है। इस मिशन के तहत दो स्पेसक्राफ्ट की अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग कराई जाएगी यानी उन्हें जोड़कर फिर अलग किया जाएगा। 7 जनवरी के आसपास यह प्रक्रिया पूरी होते ही भारत यह तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन के पास ही यह तकनीक है। डॉकिंग भारत के अपने स्पेस स्टेशन को बनाने में काम आएगी क्योंकि स्पेस स्टेशन कई मॉड्यूल से जुड़कर बनता है। इन मॉड्यूल को टुकड़ों में स्पेस में डॉकिंग के जरिए असेंबल किया जाता है। इस मिशन की कामयाबी पर ही चंद्रयान-4 मिशन निर्भर करता है क्योंकि वह वहां से सैंपल वापस लाने में उपयोगी है। स्पैडेक्स डॉकिंग तकनीक के मामले में भारत द्वारा किए गए पहले प्रयोगों में से एक है। यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मंत्र के अनुरूप इसे 'भारतीय डॉकिंग सिस्टम' नाम दिया गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्पैडेक्स मिशन इसरो की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। यह क्षमताएं भविष्य के मिशनों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनमें उपग्रह सेवा, अंतरिक्ष स्टेशन संचालन और ग्रहों के बीच के अन्वेषण शामिल हैं।



भारत वन स्थिति रिपोर्ट

वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र में 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि

भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2021 की तुलना में देश में कुल वन और वृक्ष आवरण में 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वर्तमान में जो आकलन किया गया है उसके अनुसार, कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किमी है। यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17 प्रतिशत है। वनावरण का क्षेत्रफल लगभग 7,15,343 वर्ग किमी (21.76 प्रतिशत) है जबकि वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल 1,12,014 वर्ग किमी (3.41 प्रतिशत) है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष तीन राज्य में मध्य प्रदेश (85,724 वर्ग किमी), अरुणाचल प्रदेश (67,083 वर्ग किमी) और महाराष्ट्र (65,383 वर्ग किमी) है।





'पीएलआई स्कीम'

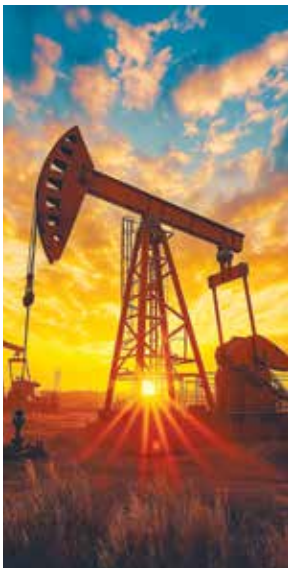
आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी रणनीतिक छलांग

आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के दृष्टिकोण से 2020 में तैयार की गई पीएलआई योजना सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी रणनीतिक छलांग है। चार वर्ष से भी कम समय में यह योजना जहां साढ़े नौ लाख से अधिक रोजगार का सृजन करने में सफल रही तो वहीं इसके जरिए 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात भी हुआ है। अगस्त 2024 तक महज 14 क्षेत्रों में ही 1.46 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, जिससे 12.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन और बिक्री रिकॉर्ड की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में 8 क्षेत्र में 2,968 करोड़ रुपये जबकि वित्त वर्ष 23-24 में 9 क्षेत्र में 6,753 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्कीम के तहत दी गई है।

आयात निर्भरता कम करने के लिए देश ने उठाए कई कदम

विश्व का एक बड़ा हिस्सा इन दिनों युद्ध और अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। लिहाजा भारत कच्चे तेल के मामले में अपनी स्थिति को मजबूत करने और दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए नीतियों में बदलाव कर रही है। बदलाव का ही नतीजा है कि पिछले दस वर्ष में ऑयल एंड मिनरल्स कॉर्पोरेशन के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) से 30 सितंबर 2024 तक लगभग 1,08,655 करोड़ रुपये से अधिक विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। सरकार ने घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए हैं। देश में ईंधन खपत में प्राकृतिक गैस की मात्रा बढ़ाई जा रही है, इथेनॉल मिश्रण, कम्प्रेस्ड बायोगैस और बायोडीजल जैसे नवीकरणीय और वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तेल शोधन प्रक्रिया में सुधार किया जा रहा है।

कच्चा तेल



50 अरब डॉलर पहुंचा, भारत का फार्मास्यूटिकल्स बाजार



वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का फार्मास्यूटिकल्स बाजार 50 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। इसमें 23.5 अरब डॉलर के उत्पाद की खपत देश में हुई जबकि 26.5 अरब डॉलर के उत्पाद निर्यात किए गए। भारत का फार्मा उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और उत्पादन मूल्य की दृष्टि से 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। भारत के फार्मास्यूटिकल्स बाजार के आकार को बढ़ाने में औषधीय और वनस्पति उत्पाद भी शामिल है। इस उद्योग में वित्त वर्ष 2022-23 के अनुसार कुल 9,25,811 लोग लगे हुए हैं। ●

75 वर्ष | भारतीय गणतंत्र



बाबा साहब अंबेडकर की प्रगतिशील और समावेशी सोच के साथ संविधान को अंगीकार कर भारत ने 26 जनवरी, 1950 को सुबह 10 बजकर 18 मिनट पर गणतंत्र राष्ट्र बनकर इतिहास रचा। गणतंत्र के रूप में विश्व के सबसे महान और विशाल लोकतंत्र की 75 वर्ष की यह यादगार यात्रा हमारे संविधान निर्माताओं के योगदान को याद करने के साथ एक उत्सव मनाने का पल है, हम सबको एक सूत्र में बांधने वाली भारतीयता के गौरव का उत्सव...

हमारे संविधान निर्माता बेहद सजग थे। वह यह नहीं मानते थे कि भारत का जन्म 1947 में हुआ है, वह यह नहीं मानते थे कि भारत में लोकतंत्र 1950 से आ रहा है। वे भारत की महान परंपरा, महान संस्कृति, महान विरासत और इसके साथ हजारों साल की अनवरत यात्रा को लेकर सजग थे। इसीलिए भारत का गणतांत्रिक अतीत बहुत ही समृद्ध रहा है। साथ ही, पूरी दुनिया के सामने उदाहरण पेश करने के साथ इसे 'मदर ऑफ डेमोक्रेसी' के रूप में जाना जाता है। भारत सिर्फ विशाल लोकतंत्र ही नहीं, लोकतंत्र की जननी हैं । इसीलिए 26 जनवरी 1950 की ऐतिहासिक तारीख और भारत के भविष्य से संबंधित युगान्तरकारी परिवर्तन के गवाह लम्हे आज भी लोगों के जेहन

> **"डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि कई चीजें संविधान में नहीं लिखी जा सकतीं, उनका संचालन परंपराओं के आधार पर किया जाता है। लगभग तीन-चौथाई सदी संवैधानिक यात्रा के दौरान भारत ने उन सार्थक परंपराओं को विकसित करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। हमने जो अनुभव हासिल किए हैं, आने वाली पीढ़ियों को उनसे अवगत कराया जाना चाहिए।**
>
> **-द्रौपदी मुर्मु, राष्ट्रपति**



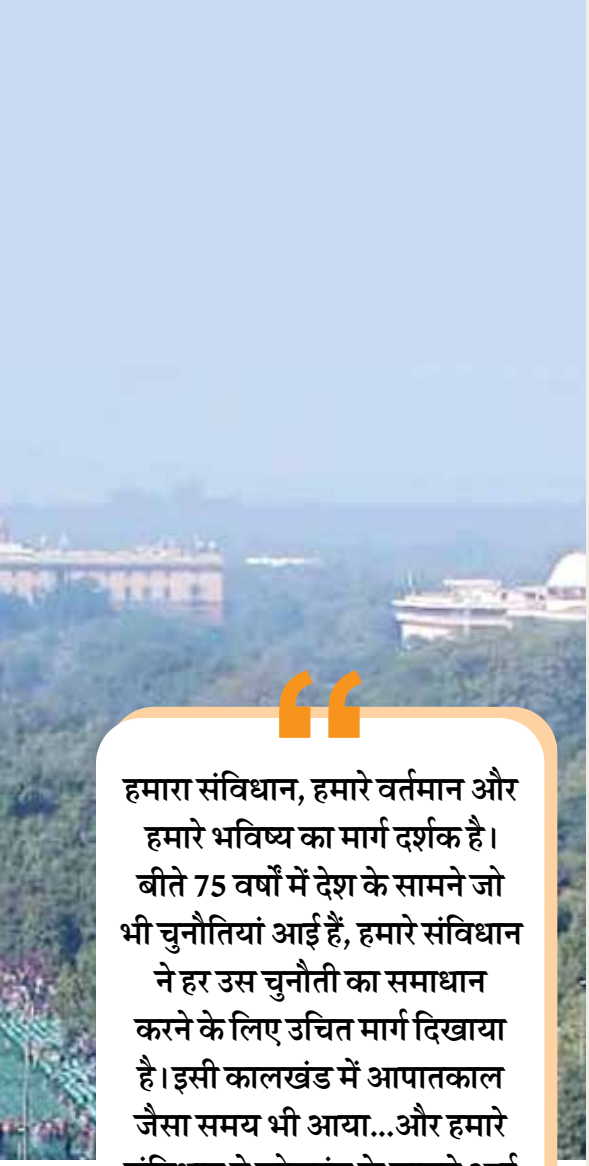
गुमनाम तारीख और नायकों को प्रणाम

गणतंत्र दिवस का यह दिन उन महानायकों को याद करने का अवसर भी है जिन्होंने स्वराज के सपने को साकार करने के लिए अतुलनीय साहस का परिचय दिया। उसके लिए देशवासियों में संघर्ष करने का उत्साह जगाया लेकिन कई ऐसी तारीख और कई ऐसे गुमनाम नायक भी हैं, जिन्हें इतिहास के पन्नों में वह स्थान नहीं मिला, जिसके वह वाकई हकदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन अहम तारीखों की पुनर्स्थापना के लिए अहम कदम उठाए हैं। राजपथ अब कर्तव्यपथ है तो संविधान को स्वीकृत करने के दिन 26 नवंबर की ऐतिहासिक तारीख को संविधान दिवस के रूप में मनाने की परंपरा की शुरुआत की गई है।









> **हमारा संविधान, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्ग दर्शक है। बीते 75 वर्षों में देश के सामने जो भी चुनौतियां आई हैं, हमारे संविधान ने हर उस चुनौती का समाधान करने के लिए उचित मार्ग दिखाया है। इसी कालखंड में आपातकाल जैसा समय भी आया...और हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का भी सामना किया। हमारा संविधान देश की हर जरूरत, हर अपेक्षा पर खरा उतरा है।**
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

में एक स्वर्णिम दस्तावेज की तरह समाये हुए हैं। बीते 75 वर्षों में देश के सामने जो भी चुनौतियां आई हैं, हमारे संविधान ने हर उस चुनौती का समाधान करने के लिए उचित मार्ग दिखाया है। इसी कालखंड में आपातकाल जैसा समय भी आया... और भारतीय लोकतंत्र ने इस चुनौती का भी सामना किया तो देश के आर्थिक एकीकरण के लिए स्वतंत्रता के बाद जीएसटी के रूप में सबसे बड़ा टैक्स सुधार, वर्ष 2018 में 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' को संवैधानिक दर्जा, महिला सशक्तीकरण

- **केंद्र सरकार पद्म पुरस्कारों को "आम लोगों का पद्म" में बदलने के लिए प्रतिबद्ध।**
- **सभी नागरिकों से आग्रह किया गया कि वे स्वयं के लिए नामांकन सहित अन्य व्यक्तियों के लिए नामांकन/सिफारिशें करें।**
- **संसद और विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित हुआ।**
- **सर्वानुमति से देश की मातृशक्ति को सम्मानित करने का काम किया।**



- **अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ 22 जनवरी, 2024 को राम मंदिर में रामलला विराजमान हुए।**

- आपातकाल के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' मनाने की शुरुआत की गई। भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है।
- देश के विभाजन के कारण अपनी जान गंवाने वाले और अपनी जड़ों से विस्थापित हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने और उनके बलिदान को याद करने के लिए सरकार ने हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस तरह के दिन की घोषणा से भारतीयों की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद आएगी।
- संविधान 103वां अधिनियम, 2019 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए हैं। यह राज्य को भारत सरकार में सिविल पदों, सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को वरीयता के आधार पर आरक्षण का लाभ प्रदान करने में सक्षम बनाता है। जनवरी 2019 में सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लागू किया।



> **हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि भारत की आकांक्षाएं, भारत के सपने समय के साथ नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। वो जानते थे कि आजाद भारत की और भारत के नागरिकों की जरूरतें बदलेंगी, चुनौतियां बदलेंगी। इसलिए उन्होंने हमारे संविधान को महज कानून की एक किताब बनाकर नहीं छोड़ा... बल्कि इसको एक जीवंत, निरंतर प्रवाहमान धारा बनाया।**
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, दंड के स्थान पर न्याय और अपराध के स्थान पर सुरक्षा की भावना पर आधारित भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे अहम कदम भी उठाए गए। इसने गणतंत्र के रूप में भारत को और मजबूत बनाने के साथ हर देशवासी में भारतीयता की भावना को प्रबल बनाने का काम किया है।

...ताकि यादगार बना रहे 'पूर्ण स्वराज दिवस'

भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया जिसे अब हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके दो महीने बाद 26 जनवरी, 1950 से हमारा संविधान पूर्णतः प्रभावी हुआ। संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस की तारीख में अंतर को लेकर मन में विचार आ सकता है कि ऐसा क्यों है? तो बताते हैं कि ऐसा सन 1930 के उस दिन को यादगार बनाने के लिए किया गया था जिस



सेंगोल : कर्तव्य पथ का प्रतीक

सेंगोल के साथ गणतंत्र की पवित्रता का पुनः अहसास सेंगोल सत्ता हस्तांतरण के साथ प्रत्येक व्यक्ति को यह स्मरण कराता है कि देश के कल्याण की जिम्मेदारी उस पर है। इस सेंगोल को एक तरह से भुला दिया गया था लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में इसे स्थापित करा नई शुरुआत की है, ताकि जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही हो, सेंगोल हम सभी को प्रेरणा दे। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्रपथ का प्रतीक माना जाता था। सी. राजगोपालाचारी और आदीनम् के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था।

कर्तव्यपथ पर दिखेगी 'स्वर्णिम भारत- विरासत और विकास' की झलक

गणतंत्र दिवस परेड-2025 के लिए कर्तव्य पथ पर अपनी झांकियां प्रदर्शित करने के लिए जिन 15 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का चयन किया गया है, उनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन व दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार के 11 मंत्रालयों/विभागों को भी गणतंत्र दिवस परेड-2025 के लिए चुना गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में झांकी की थीम 'स्वर्णिम भारत - विरासत और विकास' तय की गई है ।





दिन भारतवासियों ने पूरी आजादी हासिल करने का संकल्प लिया था। सन 1930 से 1947 तक, हर साल 26 जनवरी को 'पूर्ण स्वराज दिवस' के रूप में मनाया जाता था, अतः यह तय किया गया कि उसी दिन से संविधान को पूर्णतः प्रभावी बनाया जाए। सन 1930 में महात्मा गांधी ने देशवासियों को 'पूर्ण स्वराज दिवस' मनाने का तरीका समझाया था। उन्होंने कहा था : "... चूंकि हम अपने ध्येय को अहिंसात्मक और सच्चे उपायों से ही प्राप्त करना चाहते हैं और यह काम हम केवल आत्मशुद्धि के द्वारा ही कर सकते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि उस दिन हम अपना सारा समय यथाशक्ति कोई रचनात्मक कार्य करने में बिताएं।"

यथाशक्ति रचनात्मक कार्य करने का गांधीजी का यह उपदेश सदैव प्रासंगिक रहेगा। उनकी इच्छा के अनुसार गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाने के दिन और उसके बाद भी, हम सब की सोच और कार्यों में रचनात्मकता होनी चाहिए।

आज जब भारत परिवर्तन के इतने बड़े दौर से गुजर रहा है, देश के भविष्य का मार्ग अब बड़े सपनों, बड़े संकल्पों की सिद्धि का है। ऐसे अहम समय में भारत का संविधान ही हमें रास्ता दिखा रहा है। महात्मा गांधी कहते थे कि हम अपने भीतर झांक कर देखें, आत्म-निरीक्षण करें और बेहतर इंसान बनने का प्रयास करें। उसके बाद बाहर भी देखें, लोगों के साथ सहयोग करें और एक बेहतर भारत तथा बेहतर विश्व के निर्माण में अपना योगदान करें। यही भारतीय गणतंत्र का मूल है। ●

राष्ट्र निर्माण के 'अटल' आदर्श की शताब्दी

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री





अटल बिहारी वाजपेयी होते तो इस वर्ष सौ बरस के होते। भारतीय राजनीति में आदर्श और प्रशासन में सुशासन का अटल सिद्धांत स्थापित करने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपुरुष के रूप में अटलजी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें अपनी लेखनी की जरिए याद किया...

मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं...लौटकर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं... अटलजी के ये शब्द कितने साहसी हैं...कितने गूढ़ हैं। अटलजी, कूच से नहीं डरे... उन जैसे व्यक्तित्व को किसी से डर लगता भी नहीं था। वो यह भी कहते थे... जीवन बंजारों का डेरा आज यहां, कल कहां कूच है... कौन जानता किधर सवेरा... आज अगर वो हमारे बीच होते, तो वो अपने जन्मदिन पर नया सवेरा देख रहे होते। मैं वो दिन नहीं भूलता जब उन्होंने मुझे पास बुलाकर अंकवार में भर लिया था... और जोर से पीठ में धौल जमा दी थी। वो स्नेह... वो अपनत्व... वो प्रेम... मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है।

25 दिसंबर का यह दिन भारतीय राजनीति और भारतीय जनमानस के लिए एक तरह से सुशासन का अटल दिवस है। आज पूरा देश अपने भारत रत्न अटल को, उस आदर्श विभूति के रूप में याद कर रहा है, जिन्होंने अपनी सौम्यता, सहजता और सहृदयता से करोड़ों भारतीयों के मन में जगह बनाई। पूरा देश उनके योगदान के प्रति कृतज्ञ है। उनकी राजनीति के प्रति कृतार्थ है।

21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए उनकी एनडीए सरकार ने जो कदम उठाए, उसने देश को एक नई दिशा, नई गति दी। 1998 के जिस काल में उन्होंने पीएम पद संभाला, उस दौर में पूरा देश राजनीतिक अस्थिरता से घिरा हुआ था। 9 साल में देश ने चार बार लोकसभा के चुनाव



प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से लेकर दूरसंचार क्रांति तक उनके अहम कदमों का प्रभाव आज तक अटल है।

देखे थे। लोगों को शंका थी कि ये सरकार भी उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाएगी। ऐसे समय में एक सामान्य परिवार से आने वाले अटलजी ने, देश को स्थिरता और सुशासन का मॉडल दिया। भारत को नव विकास की गारंटी दी।

वह ऐसे नेता थे, जिनका प्रभाव आज तक अटल है। वह भविष्य के भारत के परिकल्पना पुरुष थे। उनकी सरकार ने देश को आईटी, टेलीकम्युनिकेशन और दूरसंचार की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ाया। उनके शासन काल में ही, एनडीए ने तकनीक को सामान्य मानवी की पहुंच तक लाने का काम शुरू किया। भारत के दूर-दराज के इलाकों को बड़े शहरों से जोड़ने के सफल प्रयास किए गए। वाजपेयी जी की सरकार में शुरू हुई जिस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने भारत के महानगरों को एक सूत्र में जोड़ा वो आज भी लोगों की स्मृतियों पर अमिट है। लोकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी एनडीए गठबंधन की सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे कार्यक्रम शुरू किए। उनके शासन काल में दिल्ली मेट्रो शुरू हुई, जिसका विस्तार आज हमारी सरकार एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में कर रही है। ऐसे ही प्रयासों से उन्होंने न सिर्फ आर्थिक प्रगति को नई शक्ति दी, बल्कि दूर-दराज के क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़कर भारत की एकता को भी सशक्त किया।

जब भी सर्व शिक्षा अभियान की बात होती है, तो अटलजी की सरकार का जिक्र जरूर होता है। शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानने वाले वाजपेयी जी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था, जहां हर व्यक्ति को आधुनिक और गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। वो चाहते थे ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी और महिला सभी के लिए शिक्षा सहज और सुलभ बने।

उनकी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई बड़े आर्थिक सुधार किए। इन सुधारों के कारण भाई-भतीजावाद में फंसी देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली। उस दौर की सरकार के समय में जो नीतियां बनी, उनका मूल उद्देश्य सामान्य मानवी के जीवन को बदलना ही रहा। उन्होंने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया, ये पुराना भारत नहीं है। पूरी दुनिया जान चुकी थी कि भारत अब दबाव में आने वाला देश नहीं है। इस परमाणु परीक्षण की वजह से देश पर प्रतिबंध भी लगे, लेकिन देश ने सबका मुकाबला किया।

उनकी सरकार के कई ऐसे अद्भुत और साहसी उदाहरण हैं, जिन्हें आज भी हम देशवासी गर्व से याद करते है। देश को अब भी 11 मई 1998 का वो गौरव दिवस याद है, एनडीए सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण हुआ। इसे 'ऑपरेशन शक्ति' का नाम दिया गया। इस परीक्षण के बाद दुनियाभर में भारत के वैज्ञानिकों को लेकर चर्चा होने लगी। इस बीच कई देशों ने खुलकर नाराजगी जताई,





पोखरण में उनके मजबूत संकल्प की झलक पूरी दुनिया ने देखी तो अर्थव्यवस्था को गति देने वाले उनके अटल इरादों को भी सराहा।

लेकिन तब की सरकार ने किसी दबाव की परवाह नहीं की। पीछे हटने की जगह 13 मई को न्यूक्लियर टेस्ट का एक और धमाका कर दिया गया। 11 मई को हुए परीक्षण ने तो दुनिया को भारत के वैज्ञानिकों की शक्ति से परिचय कराया था। लेकिन 13 मई को हुए परीक्षण ने दुनिया को यह दिखाया कि भारत का नेतृत्व एक ऐसे नेता के हाथ में है, जो एक अलग मिट्टी से बना है।

वाजपेयी सरकार के शासन काल में कई बार सुरक्षा संबंधी चुनौतियां आईं। करगिल युद्ध का दौर आया। संसद पर आतंकियों ने कायरना प्रहार किया। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले से वैश्विक स्थितियां बदलीं, लेकिन हर स्थिति में अटलजी के लिए भारत और भारत का हित सर्वोपरि रहा। जब भी आप वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के बारे में किसी से बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि वो लोगों को अपनी तरफ खींच लेते थे। उनकी बोलने की कला का कोई सानी नहीं था। कविता और शब्दों में उनका कोई जवाब नहीं था। विरोधी भी वाजपेयी जी के भाषण के मुरीद थे। युवा सांसदों के लिए वो चर्चाएं सीखने का माध्यम बनतीं।

कुछ सांसदों की संख्या लेकर भी, वो कांग्रेस की कुनीतियों का प्रखर विरोध करने में सफल होते। भारतीय राजनीति में वाजपेयी जी ने दिखाया, ईमानदारी और नीतिगत स्पष्टता का अर्थ क्या है। संसद में कहा गया उनका ये वाक्य... सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी मगर यह देश रहना चाहिए... आज भी मंत्र की तरह हम सबके मन में गूंजता रहता है।

वह भारतीय लोकतंत्र को समझते थे। वह यह भी जानते थे कि लोकतंत्र का मजबूत रहना कितना जरूरी है। आपातकाल के समय उन्होंने दमनकारी कांग्रेस सरकार का जमकर विरोध किया, यातनाएं झेली। जेल जाकर भी संविधान के हित का संकल्प दोहराया। एनडीए की स्थापना के साथ उन्होंने गठबंधन की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित किया। वह अनेक दलों को साथ लाए और एनडीए को विकास, देश की प्रगति और



क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधि बनाया। पीएम पद पर रहते हुए उन्होंने विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब हमेशा बेहतरीन तरीके से दिया। वह ज्यादातर समय विपक्षी दल में रहे, लेकिन नीतियों का विरोध तर्कों और शब्दों से किया। एक समय उन्हें कांग्रेस ने गद्दार तक कह दिया था, उसके बाद भी उन्होंने कभी असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उनमें सत्ता की लालसा नहीं थी। 1996 में उन्होंने जोड़-तोड़ की राजनीति न चुनकर, इस्तीफा देने का रास्ता चुन लिया। राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण 1999 में उन्हें सिर्फ एक वोट के अंतर के कारण पद से इस्तीफा देना पड़ा। कई लोगों ने उनसे इस तरह की अनैतिक राजनीति को चुनौती देने के लिए कहा, लेकिन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी शुचिता की राजनीति पर चले। अगले चुनाव में उन्होंने मजबूत जनादेश के साथ वापसी की।

संविधान के मूल्य संरक्षण में भी, उनके जैसा कोई नहीं था। डॉ. श्यामा प्रसाद के निधन का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। वह आपातकाल के खिलाफ लड़ाई का भी बड़ा चेहरा बने। आपातकाल के बाद 1977 के चुनाव से पहले उन्होंने 'जनसंघ' का जनता पार्टी में विलय करने पर भी सहमति जता दी। मैं जानता हूं कि यह निर्णय सहज नहीं रहा होगा, लेकिन वाजपेयी जी के लिए हर राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता की तरह दल से बड़ा देश था, संगठन से बड़ा, संविधान था।

हम सब जानते हैं, अटलजी को भारतीय संस्कृति से भी बहुत लगाव था। भारत के विदेश मंत्री बनने के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देने का अवसर आया, तो उन्होंने अपनी हिंदी से पूरे देश को खुद से जोड़ा। पहली बार किसी ने हिंदी में संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात कही। उन्होंने भारत की विरासत को विश्व पटल पर रखा। उन्होंने सामान्य भारतीय की भाषा को संयुक्त राष्ट्र के मंच तक पहुंचाया। राजनीतिक जीवन में होने के बाद भी, वह साहित्य और अभिव्यक्ति से जुड़े रहे। वह एक ऐसे कवि और लेखक थे, जिनके शब्द हर विपरीत स्थिति में व्यक्ति को आशा और नव सृजन की प्रेरणा देते थे। वह हर उम्र-हर वर्ग के प्रिय और अपने थे।



जब भी सत्ता और विचारधारा के बीच एक को चुनने की स्थितियां आई, अटलजी ने हमेशा खुले मन से विचारधारा को ही चुना।

मेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं को उनसे सीखने का, उनके साथ काम करने का, उनसे संवाद करने का अवसर मिला। अगर आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो इसका श्रेय उस अटल आधार को है, जिसपर ये दृढ़ संगठन खड़ा है। उन्होंने बीजेपी की नींव तब रखी, जब कांग्रेस जैसी पार्टी का विकल्प बनना आसान नहीं था। उनका नेतृत्व, उनकी राजनीतिक दक्षता, साहस और लोकतंत्र के प्रति उनके अगाध समर्पण ने भाजपा को भारत की लोकप्रिय पार्टी के रूप में प्रशस्त किया। लालकृष्ण आडवाणी और डॉ. मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों के साथ, उन्होंने पार्टी को अनेक चुनौतियों से निकालकर सफलता के सोपान तक पहुंचाया।

जब भी सत्ता और विचारधारा के बीच एक को चुनने की स्थितियां आईं, उन्होंने इस चुनाव में विचारधारा को खुले मन से चुन लिया। वह देश को यह समझाने में सफल हुए कि कांग्रेस के दृष्टिकोण से अलग एक वैकल्पिक वैश्विक दृष्टिकोण संभव है। ऐसा दृष्टिकोण वास्तव में परिणाम दे सकता है। आज उनका रोपित बीज, एक वटवृक्ष बनकर राष्ट्र सेवा की नव पीढ़ी को रच रहा है। अटलजी की 100वीं जयंती, भारत में सुशासन के एक राष्ट्र पुरुष की जयंती है। आइए हम सब इस अवसर पर, उनके सपनों को साकार करने के लिए मिलकर काम करें। हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें, जो सुशासन, एकता और गति के अटल सिद्धांतों का प्रतीक हो। मुझे विश्वास है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिखाए सिद्धांत ऐसे ही, हमें भारत को नव प्रगति और समृद्धि के पथ पर प्रशस्त करने की प्रेरणा देते रहेंगे। ●

वास्तुकला की दुनिया का ध्रुवतारा

इमारतें केवल किसी जगह को आधुनिक रूप ही नहीं देतीं। यह महत्वकांक्षा को उपलब्धि और आशावाद को अवसर से भी जोड़ती हैं। भारत के मशहूर वास्तुकार डॉ. बालकृष्ण विट्ठलदास दोशी ने इसे साबित भी किया। उन्होंने न केवल देश की कई प्रतिष्ठित इमारतों को डिजाइन किया, बल्कि जीवनशैली और पर्यावरण को ध्यान में रख सबसे सस्ते घर के तौर पर 'अरण्य' को बना अपने घर के सपने को नई उम्मीद दी। शायद इसलिए उन्हें दुनिया में वास्तुकला का ध्रुवतारा कहा जाता है।

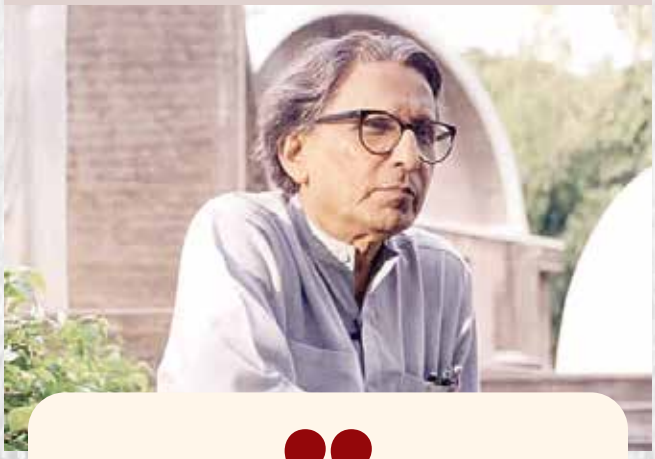
26 अगस्त 1927 को पुणे में डॉ. बालकृष्ण विट्ठलदास दोशी का जन्म हुआ। दोशी परिवार के पास एक फर्नीचर की वर्कशॉप थी। परिवार को लगता था कि बेटा भी इसी पेशे को अपनाएगा। लेकिन, बालकृष्ण का मन वास्तुकला में रमा। उन्होंने 1947 में मुंबई के प्रतिष्ठित सर जेजे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में दाखिला लिया। 1950 में लंदन चले गए। दोशी का प्रतिष्ठित कॅरिअर छह दशकों से अधिक समय तक रहा है। इसमें 100 से अधिक परियोजनाएं सम्मिलित हैं।

1950 के दशक में उन्होंने चंडीगढ़ के लिए योजना बनाने में मदद करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मास्टर ली कोर्बुजियर के साथ काम किया और 1960 के दशक में आईआईएम अहमदाबाद की रूपरेखा पर लुई कान के सहयोगी के रूप में काम किया। अंततः दोशी ने स्वयं के वास्तुशिल्प कार्यालय की शुरुआत की और पर्यावरणीय परिस्थितियों से उत्पन्न क्षेत्रीय प्रभावों के साथ जीवन की जरूरतों को जोड़ते हुए एक नई शैली तैयार की। इसके बाद उन्होंने आईआईएम बंगलूरू और लखनऊ, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, टैगोर मेमोरियल हॉल, अहमदाबाद का द इंस्टिट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के अलावा भारत भर में कई कैंपस और इमारतों को डिजाइन किया।

डॉ. दोशी इमारतों को अपने जीवन का दर्शन और सपनों का विस्तार मानते थे। उन्हें आधुनिकतावादी वास्तुकला का अग्रदूत और भारत का पहला आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। बालकृष्ण दोशी ने अपने 6 दशक से अधिक के कॅरियर में 100 से अधिक प्रोजेक्ट पूरे किए। वह चाहते थे कि उनकी इमारतें सिर्फ देखने में सुंदर न हो, बल्कि उससे ज्यादा कुछ हों और इसीलिए वे वास्तुकला को ढांचों का जीवित नमूना मानते थे। 1980 के दशक में मध्य प्रदेश के इंदौर में उन्होंने लोगों के लिए बेहद कम लागत वाले मकान की नई अवधारणा पेश की। 'अरण्य' नाम से तैयार एक कमरे के इन मकानों के लिए उन्हें प्रतिष्ठित आगा खां पुरस्कार से नवाजा गया। इसके साथ ही वह ऐसे पहले भारतीय बने जिन्हें 2018 में आर्किटेक्चर का प्रतिष्ठित प्रित्जकर पुरस्कार दिया गया। इसे आर्किटेक्चर का नोबल भी कहा जाता है। उन्हें 2022 में यूके के रॉयल गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया था।

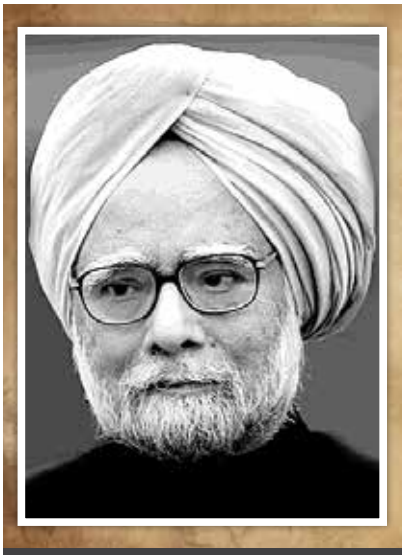
डॉ. दोशी को वर्ष 2020 में पद्म भूषण दिया गया था। 24 जनवरी 2023 को करीब 95 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। वर्ष 2023 में (मरणोपरांत) पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। ●

जन्म : 26 अगस्त 1927, मृत्यु : 24 जनवरी 2023



डॉ. बालकृष्ण दोशी जी एक प्रतिभाशाली वास्तुकार और एक उल्लेखनीय संस्था-निर्माता थे। आने वाली पीढ़ियों को, भारत भर में उनके समृद्ध कार्यों की प्रशंसा करते हुए, उनकी महानता की झलक प्राप्त होगी। – नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री





जन्म : 26 सितंबर 1932
मृत्यु : 26 दिसंबर 2024

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि

भारत के आर्थिक उदारीकरण के वास्तुकार

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर को दिल्ली एम्स में निधन हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से लेकर देश के वित्त मंत्री और 10 वर्ष तक लगातार प्रधानमंत्री के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह ने देश की शासन व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए विद्वान अर्थशास्त्री और सुधारों के लिए समर्पित नेता के रूप में किया याद...

आर्थिक उदारीकरण के नायक माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक शिक्षाविद् और नौकरशाह के रूप में तो काम किया ही, सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में भी योगदान दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में 26 सितंबर 1932 को डॉ. मनमोहन सिंह का जन्म हुआ। यह हिस्सा अब पाकिस्तान में है। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा, "पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह उन दुर्लभ राजनेताओं में से एक थे, जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में भी समान सहजता से काम किया। सरकारी कार्यालयों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा, उनके बेदाग राजनीतिक जीवन और अत्यंत विनम्रता के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उनका निधन हम सभी के लिए बहुत बड़ी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने डॉ. मनमोहन सिंह के सानिध्य में अपने छात्र जीवन को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। डॉ. मिश्रा ने कहा, जिस समय डॉ. मनमोहन सिंह दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में पढ़ाते थे। मैं उन दिनों एम.ए. प्रथम वर्ष में था। यह वह दौर था, जब इस प्रतिष्ठित संस्थान में अमर्त्य सेन, मृणाल दत्ता चौधरी, ए.एम. खुसरो, के.एन. राज, सुखमय चक्रवर्ती औरी धर्म कुमार जैसे बेहतरीन शिक्षक हुआ करते थे। डॉ. मनमोहन सिंह में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जटिल विषयों को हर छात्र की समझ में आने वाले तरीके से समझाने की अद्भुत क्षमता थी, जिससे छात्रों के लिए सीखना आसान हो जाता था।



क्षति है। मैं भारत के सबसे महान सपूतों में से एक को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं।"

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह के निधन से गहरा दुख हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री और एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। 1991 में भारत के आर्थिक उदारीकरण के वास्तुकार ने साहसपूर्वक देश को महत्वपूर्ण परिवर्तन के माध्यम से आगे बढ़ाया, विकास और समृद्धि के लिए नए रास्ते खोले।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि दी और कहा, "उनके निधन से हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंची है। उनका जाना राष्ट्र के लिए बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, यह सामान्य बात नहीं है। अभाव और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन यह सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा।" पीएम मोदी ने कहा कि एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग-अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दीं। चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट के दौरान देश को नई राह दिखाई।

पीएम मोदी ने डॉ. सिंह को याद करते हुए कहा कि जनता और देश के विकास के प्रति जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। उनका जीवन ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। विनम्रता, सौम्यता और बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान रही। पीएम मोदी ने कहा कि साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉ. सिंह की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। संसद सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हील चेयर पर बैठकर आते थे और अपना संसदीय दायित्व निभाते थे।

दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थान से शिक्षा लेने और सरकार में अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी डॉ. सिंह अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा और सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। पीएम मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते वे डॉ. मनमोहन सिंह के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विषयों पर खुले मन से चर्चा करते थे। दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय-समय पर बात और मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पूर्व-प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की स्मृति में शोक प्रस्ताव पारित किया और दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

सात दिन का राजकीय शोक घोषित

दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के सम्मान में पूरे भारत में 26.12.2024 से 01.01.2025 तक सात दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। इस अवधि के दौरान पूरे भारत में उन स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा, जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता है और राजकीय शोक की अवधि के दौरान कोई आधिकारिक उत्सव नहीं होगा। दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। विदेश में सभी भारतीय मिशन, भारतीय उच्चायोग में भी अंतिम संस्कार के दिन राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा।



27 जनवरी : बोडो समझौते की छठी वर्षगांठ

शांति समझौते के बाद बोडोलैंड में विकास की नई लहर

तकरीबन पांच साल पहले गृह मंत्री अमित शाह ने असम के प्रतिबंधित बोडो समूह के साथ समझौते की घोषणा की तो पूर्वोत्तर में इसे उज्ज्वल भविष्य की एक नई सुबह कहा गया। यही वह आधार भी था, जिस पर आगे बढ़कर दूसरे कई शांति समझौतों की नींव रखी गई। हिंसा का रास्ता छोड़ युवाओं ने देश के विकास में योगदान देने की शपथ ली तो समृद्धि और विकास की नई जमीन भी तैयार हुई। इसी नींव को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 दिसंबर को अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद की बैठक में लिया भाग...

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं पूर्वोत्तर को प्रमुखता दी तो स्वाभाविक रूप से यह क्षेत्र पूरी केंद्र सरकार की प्राथमिकता बन गया। आज यह क्षेत्र अनेक विविधताओं के बावजूद निरंतर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। 27 जनवरी 2020 को हुए बोडो शांति समझौते ने भी न केवल बोडोलैंड को दशकों से चले आ रहे संघर्ष, हिंसा और जनहानि के दौर से निजात दिलाई बल्कि इस क्षेत्र के लिए प्रगति का आधार स्तंभ भी बना।

त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) की 72वीं पूर्ण बैठक में इसका जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार इस क्षेत्र को दुनिया के फोकस में लाकर खड़ा किया है, वह पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए युगांतकारी है। लंबे समय तक यह क्षेत्र दिल्ली के लिए सिर्फ भाषणों का मुद्दा रहा था लेकिन पीएम मोदी ने अपने विजन और संवेदनशीलता से इस क्षेत्र को विकास के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। पिछले 10 साल में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के कारण जहां दिल्ली से पूर्वोत्तर की भौगोलिक दूरी कम हुई है, वहीं पीएम मोदी ने दिलों की दूरी को भी कम किया है। पूर्वोत्तर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता कि अब तक 65 दौरे कर वह इस क्षेत्र में सबसे

पूर्वोत्तर में शांति और विकास के लिए हुए प्रमुख समझौते





29 नवंबर 2023
मणिपुर के सबसे पुराने सशस्त्र समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ भारत सरकार और मणिपुर सरकार का शांति समझौता।

27 जनवरी, 2020
भारत सरकार, असम सरकार और बोडो समूह के प्रतिनिधियों के बीच समझौता।

4 सितंबर 202
कार्बी-आंगलोंग समझौता, वर्षों पुराने असम के कार्वी क्षेत्र के विवाद को हल किया।

20 अप्रैल 2023
असम-अरुणाचल प्रदेश अंतरराज्यीय सीमा समझौता।

29 दिसंबर, 2023
भारत सरकार, असम और उल्फा के बीच समझौता।

29 मार्च 2022
असम और मेघालय राज्य की सीमा के संदर्भ में समझौता।

27 अप्रैल, 2023
केंद्र सरकार, असम सरकार एवं दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के बीच त्रिपक्षीय समझौता।

10 अगस्त 2019
त्रिपुरा में उग्रवादियों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए एनएलएफटी (एसडी) से समझौता।





16 जनवरी 2020
23 साल पुराने ब्रु-रिआंग शरणार्थी संकट समाधान के लिए केंद्र, त्रिपुरा, मिजोरम सरकार और ब्रु-रिआंग प्रतिनिधियों का समझौता।

> **"पिछले 10 साल में नॉर्थ ईस्ट में हिंसक घटनाओं में 71% और नागरिकों की मृत्यु में 86% की कमी दर्ज की गई है। 10,574 विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया है। कई शांति समझौतों के कारण पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित करने में भारत सरकार को सफलता मिली है।**
>
> – अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

हजारों नौजवानों ने हिंसा छोड़कर अपनाया विकास का रास्ता

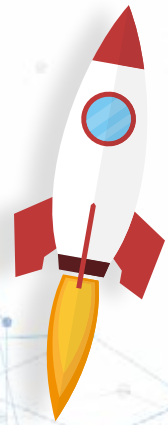
पिछले 10 साल में पूर्वोत्तर के हर राज्य में स्थाई शांति के लिए कई ऐतिहासिक समझौते हुए हैं। साथ ही, केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्रयासों से 10,574 हथियारबंद युवा आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। इससे पूर्वोत्तर में शांति आई है एवं विकास की नींव पड़ी है। एक अभूतपूर्व जनसमर्थन दिख रहा है। राज्यों के बीच जो सीमा विवाद थे, उनमें भी काफी सौहार्दपूर्ण ढंग से प्रगति हुई अनेक जिलों से अफ्स्पा को हटाया जा चुका है।

ज्यादा बार जाने वाले पीएम हैं तो विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों ने भी यहां 700 दिनों से अधिक का रात्रि प्रवास किया है।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चार दशकों तक नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की पुलिस का पूर्ण फोकस उग्रवाद के साथ लड़ने पर रहा है और अब जबकि उग्रवाद नहीं है, तब हमें नागरिकों को उनके अधिकार प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करके नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों को संविधान प्रदत्त अधिकार दे पाएंगे।

विशिष्ट रणनीति के साथ बढ़े आगे

सुरक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को अपनाया है और हर राज्य के लिए एक विशिष्ट रणनीति बनाकर पिछले 10 साल में आगे बढ़ा है। इस रणनीति का ही परिणाम है कि पुलिस, सेना, असम राइफल्स और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने मिलकर पूर्वोत्तर में एक बहुत अच्छी व्यवस्था स्थापित करने में सफलता पाई है। पिछले 10 साल में पूर्वोत्तर में हिंसक घटनाओं में 71% और नागरिकों की मृत्यु में 86% की कमी हुई है। ●



स्टार्टअप हब

बनता नया भारत



वर्ष 2014 में जब देश का मिजाज बदला तो पहली बार कई नए शब्द सुनने में आए! स्टार्टअप... एक ऐसा ही शब्द है... लेकिन इनोवेशन और इंक्यूबेशन के रास्ते युवा सपनों की तकदीर बदलने में विश्वास करने वाली केंद्र सरकार के प्रयासों की बदौलत डेढ़ लाख से अधिक स्टार्टअप के साथ भारत अब इस मामले में दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत व्यवस्था है। यह संभव हुआ है स्टार्टअप इंडिया के जरिए... आपकी उम्मीदों को नए पंख देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहल 16 जनवरी को सफलता के 9 साल पूरे कर रही है...

सफलता की कहानी

आइसोनॉमी लीगल-251

क्या आप कानून से जुड़ी सेवाओं की खोज में अभी तक उलझे हुए हैं तो आपके लिए आइसोनॉमी लीगल-251 काफी उपयोगी साबित हो सकता है। यह कानून और प्रौद्योगिकी के जरिए लोगों को समाधान मुहैया कराने वाला एक अनूठा और अभिनव स्टार्टअप है। इसकी स्थापना कानूनी सेवाओं को अधिक सुलभ, कुशल और सस्ती बनाने की दृष्टि से की गई थी, खासकर उन लोगों के लिए जो कानूनी प्रणाली तक पहुंच से वंचित हैं। इसके संस्थापक कन्हैया शर्मा कहते हैं कि हमारे देश में बहुत लोग कानूनी दुनिया की जटिलता और महंगी व्यवस्था के बीच उलझ कर रह जाते हैं। इस वजह से उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। 'आइसोनॉमी' नाम कानूनी प्रणाली में 'समानता' की अवधारणा से लिया गया है, जो कानूनी सेवाओं तक पहुंच को कंपनी के मिशन को दर्शाता है।





1.54 लाख+

मान्यता प्राप्त स्टार्टअप



एक युवा के सामने यह सवाल सबसे आम है। लेकिन, आज से नौ या दस वर्ष पहले यह जवाब उतना आम नहीं था।

भारत जैसा युवा देश, जहां रहने वाली 65 फीसदी आबादी औसत 35 वर्ष के युवाओं की है, जरूरत थी इन युवा सपनों की आकांक्षाओं को एक बेहतर और सही रास्ता दिखाने की। इसी सोच और जज्बे को सही मंजिल मिली 15 अगस्त 2015 को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 'स्टार्टअप इंडिया' की घोषणा की। करीब पांच महीने के भीतर ही 16 जनवरी 2016 को इसकी औपचारिक शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा, "जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता। जो करता है, उसी को दिखता है कि क्या होने वाला है। मेरा सपना है देश का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने।"

आज 1.54 लाख से अधिक स्टार्टअप के साथ-साथ 118 से अधिक यूनिकॉर्न 'स्टार्टअप इंडिया' की सफलता की कहानी बयां कर रहे हैं। साधारण शब्दों में कहें तो स्टार्टअप का अर्थ होता है नई कंपनी को शुरू करना जिसमें दैनिक समस्याओं के नवाचार के जरिये समाधान खोजे जाते हैं। ऐसी कंपनियों को युवा उद्यमी स्वयं या दो तीन लोगों के साथ मिलकर शुरू करते हैं। भारत आज अगर ग्लोबल स्टार्टअप की दुनिया के लिए नई उम्मीद, नई ताकत बनकर उभरा है तो इसके पीछे एक सोची-समझी



जनवरी 2016

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की, 19 बिंदुओं पर स्टार्टअप इंडिया का एक्शन प्लान जारी।

मार्च 2016

स्टार्टअप इंडिया पोर्टल **http://startupindia.gov.in** और मोबाइल एप लॉन्च। पंजीकरण-अनुपालन में मदद मिली।

जुलाई 2016

फंड ऑफ फंड्स की स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपये के फंड के साथ की गई स्थापना।

अप्रैल 2017

स्टार्टअप को कर लाभ देने के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन किया गया।

जून 2017

स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन हब लॉन्च। स्टार्टअप के सभी हितधारकों को कनेक्ट करने का प्लेटफार्म है।

सितंबर 2019

DPIIT ने स्टार्टअप को मान्यता देने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू किया।

फरवरी 2019

स्टार्टअप को मान्यता दी जाने वाली पात्रता शर्तें जारी की गईं।

अप्रैल 2018

स्टार्टअप पेटेंट प्रोटेक्शन स्कीम लागू की गई, जिसमें स्टार्टअप के लिए पेटेंट शुल्क में 80% छूट दी गई।

जनवरी 2020

स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन, नवोन्मेषण और स्टार्टअप को बढ़ावा देने और मजबूत इको सिस्टम पर सरकार को सलाह देते हैं।

जनवरी 2021

स्टार्टअप इंडिया-आगे का रास्ता लांच किया गया, स्टार्टअप इंडिया के 5 वर्ष पूरे होने पर। इसमें कई पहल शामिल।

अप्रैल 2021

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत, 2021-22 से 4 वर्ष की अवधि के लिए 945 करोड़ रुपये स्वीकृत।

मार्च 2022

भारत में पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या 75,000 को पार कर गई।

जनवरी 2022

स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए 'राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस' मनाने की घोषणा।

जून 2021

भारत में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 50,000 के पार पहुंची।

सितंबर 2023

भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या 100 पार, इनका संयुक्त मूल्यांकन 347 अरब डॉलर से ज्यादा।

सितंबर 2024

भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री-भास्कर का शुभारंभ, केंद्रीय वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा।

नवंबर 2024

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 1,50,000+ पहुंची।

सफलता की कहानी
आंकड़ों की जुबानी



1.54 लाख+
मान्यता प्राप्त स्टार्टअप

5,000
स्टार्टअप ने कराए हैं पेटेंट

36%
वृद्धि हुई मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में 2023 से 2024 के बीच

48%
मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में हैं कम से कम एक महिला निदेशक

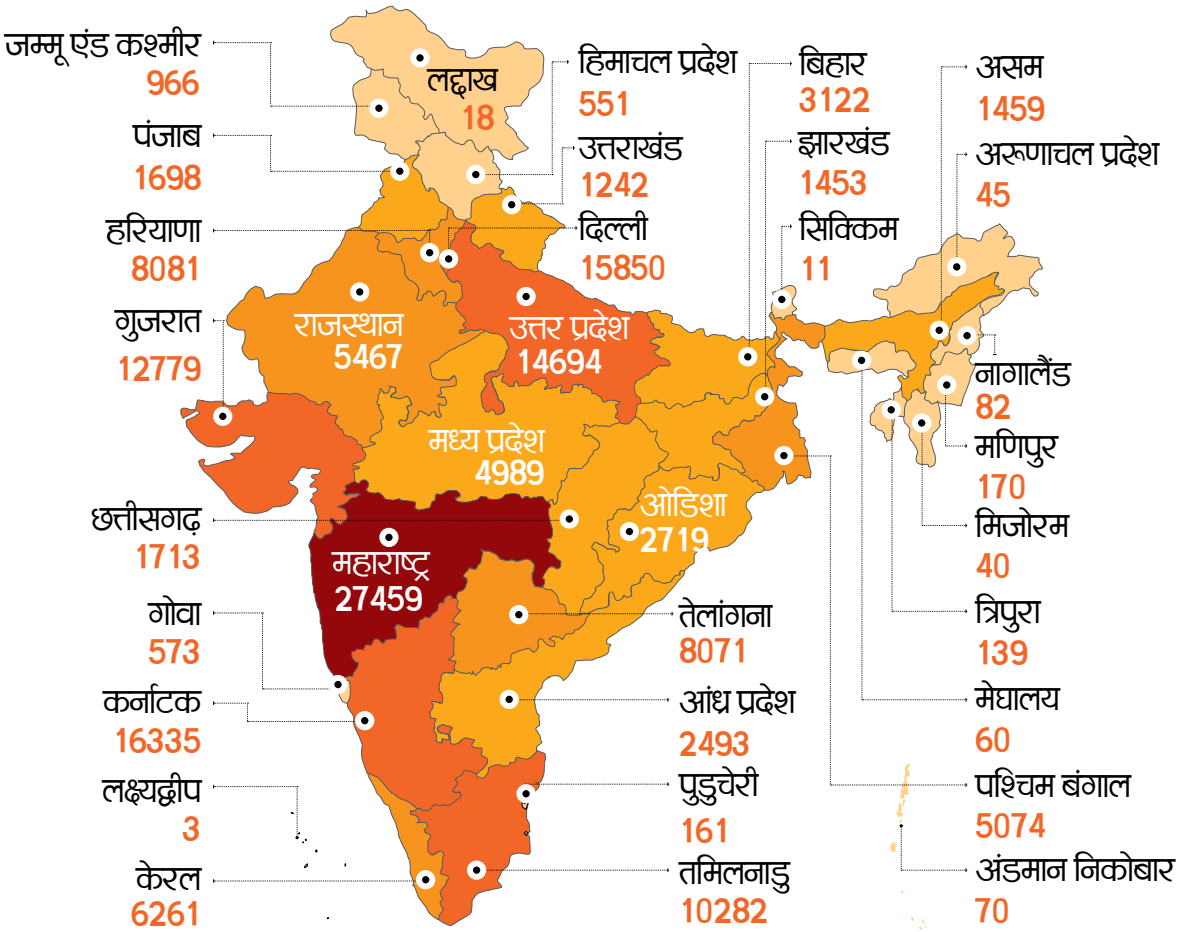
110+
स्टार्टअप को हर दिन मिल रही है मान्यता

50%
स्टार्टअप टियर-2 और टियर-3 शहरों में

130%+
चक्रवृद्धि वृद्धि दर रही मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की

2583 से ज्यादा स्टार्टअप ने सीड फंड योजना का लाभ लिया

राज्यवार स्टार्टअप की संख्या

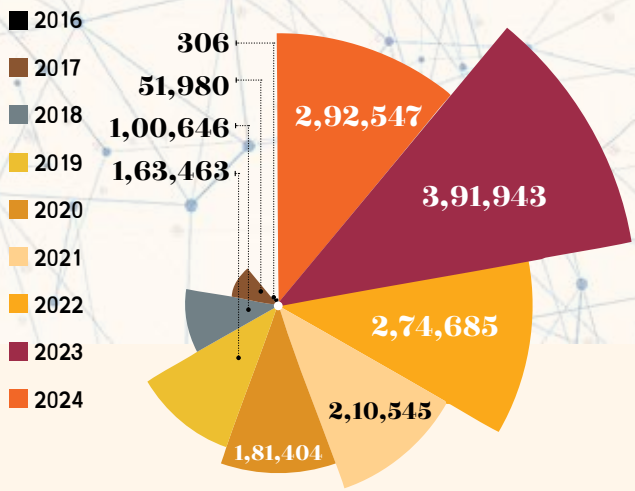


आंकड़े 30 नवंबर 2024 तक

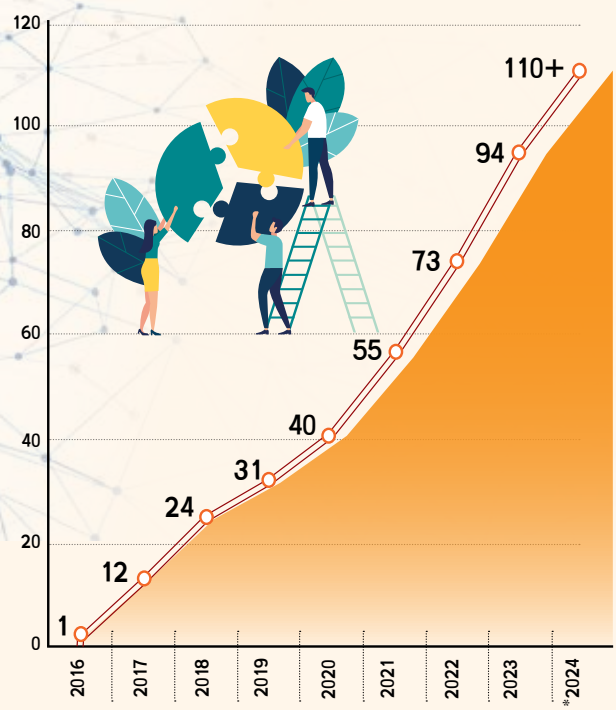
कदम-दर-कदम लगातार बढ़ते
सफलता के चरण

बड़ी संख्या में रोजगार सृजन का माध्यम बने स्टार्टअप

16.67 लाख से अधिक लोगों को मिला है प्रत्यक्ष रोजगार



हर दिन जुड़े मान्यता प्राप्त स्टार्टअप



नोटः *2024 का आंकड़ा 31 अक्टूबर, 2024 तक है।

दूरदर्शिता रही है। भारत ने सही समय पर सही निर्णय लिए और सही समय पर स्टार्टअप को लेकर काम शुरू किया। देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत इनोवेटिव आइडियाज को एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको फंडिंग के स्रोतों से जोड़ा और शिक्षण संस्थानों में अटल टिंकरिंग लैब जैसे बेहतरीन इन्क्यूबेटर्स स्थापित करने का अभियान भी चलाया। आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि स्टार्टअप ईको-सिस्टम केवल बड़े मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं है। यह देश के 600 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। भारत की स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व आज देश के छोटे शहरों के युवा कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि स्टार्टअप केवल तकनीक तक ही सीमित हैं लेकिन सच्चाई यह है कि आज कृषि, टेक्सटाइल, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट और स्पेस के साथ-साथ योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में भी स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं।

सफलता की कहानी

स्काईरूट

हैदराबाद स्थित यह स्टार्टअप पेसे लॉन्च व्हीकल विकसित कर रहा है जो अंतरिक्ष में छोटे पेलोड लेकर जाएंगे। इससे अंतरिक्ष प्रक्षेपण की लागत बहुत कम होने का अनुमान है। 'स्काईरूट एयरोस्पेस' पहला अंतरिक्ष स्टार्टअप था जिसने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी उद्यमियों के लिए खोले जाने के बाद श्रीहरिकोटा में इसरो स्टेशन से एक निजी रॉकेट लॉन्च किया था। आईआईटी से पासआउट दो विशेषज्ञ पवन और भरत के नेतृत्व में अत्याधुनिक तकनीक के साथ भारत की सबसे बड़ी रॉकेट विकास सुविधा स्थापित की गई है।

सफलता की कहानी

तगड़ा रहो

ऋषभ मल्होत्रा बेंगलुरु के रहने वाले हैं और उनका स्टार्टअप है 'तगड़ा रहो'। वह बताते हैं कि हमारा स्टार्टअप भारत के पारंपरिक व्यायाम को आगे लाने के लिए बनाया गया है। भारत के पारंपरिक व्यायाम में एक बहुत ही अद्भुत व्यायाम है 'गदा व्यायाम'। इसका पूरा फोकस गदा और मुग्दर व्यायाम पर ही है। गदा व्यायाम हजारों साल पुराना व्यायाम है। 'तगड़ा रहो' के माध्यम से ऋषभ इसे एक आधुनिक फोरम में वापस लेकर आए हैं।

आज ट्रेनिंग के अलावा नौजवानों को स्टार्टअप इंडिया अभियान के जरिए आर्थिक मदद भी दी जा रही है। टैक्स में भी छूट दी जा रही है। नौजवानों को बिजनेस के लिए 20 लाख रुपये तक के मुद्रा लोन की भी व्यवस्था की गई है। नई कंपनियों के लिए देशभर में टेक्नोलॉजी पार्क और नए आईटी हब बनाए जा रहे हैं। सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये का रिसर्च फंड भी बनाया है। यानी करियर की हर स्टेज पर सरकार नौजवानों के साथ खड़ी है और उनकी जरूरतों के हिसाब से काम कर रही है।

नए भारत का आधार स्तंभ बने स्टार्टअप-यूनिकॉर्न

भारत में नया करने की, नए आइडिया से समस्याओं के समाधान की इच्छाशक्ति हमेशा रही है लेकिन 2014 से पहले देश के नेतृत्व ने ऐसा माहौल और स्पष्ट नीति नहीं दी, जिससे समस्याओं के नए और इनोवेटिव समाधान जमीन पर उतर पाते। 2014 में नेतृत्व बदला तो देश में नव प्रयोग और मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के 9 साल के इस कालखंड में स्टार्टअप की कहानी बदल चुकी है। 'भारत के लिए इनोवेशन' और 'भारत से इनोवेशन' का मंत्र लेकर स्टार्टअप नए भारत के आधारस्तंभ बन रहे हैं और दुनिया का नेतृत्व भी कर रहे हैं। स्टार्टअप में बढ़ती ताकत और कार्य संस्कृति को देश के हर हिस्से में पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस



इन सेक्टर पर ज्यादा भरोसा
मान्यता प्राप्त स्टार्टअप

17,600
से ज्यादा स्टार्टअप आईटी सेवा से जुड़े हुए हैं।

14,285
हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस।

9,000 शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं।

15,870
स्टार्टअप जिनमें हैं एक से अधिक महिला निदेशक

1,700
से ज्यादा स्टार्टअप को नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत दी गई सहायता

रोजगार पैदा करने वाले टॉप 5 स्टार्टअप

आईटी सेवाएं	2,04,119
स्वास्थ्य देखभाल और लाइफ साइंसेस	1,47,639
व्यावसायिक और वाणिज्यिक सेवाएं	94,060
शिक्षा	90,414
निर्माण	88,702

मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए पात्रता मानदंड

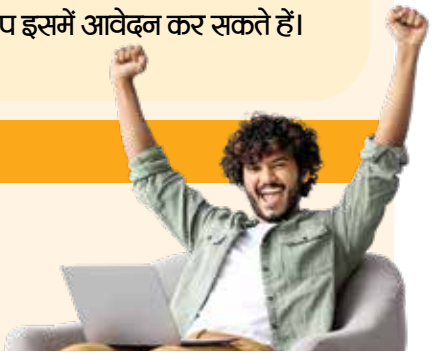
- स्टार्टअप को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में संस्थापित होना चाहिए या पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- पिछले किसी भी वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपये से कम का कारोबार होना चाहिए।
- किसी भी संस्था को अनकॉर्पोरेट की तिथि से अगले 10 वर्ष तक स्टार्टअप माना जाएगा।
- स्टार्टअप को मौजूदा प्रोडक्ट, सर्विसेज और प्रोसेस के सुधार की दिशा में काम करना चाहिए। रोजगार/धन उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। किसी मौजूदा बिजनेस के विभाजन या पुनर्निर्माण द्वारा बनाई गई संस्था को 'स्टार्टअप' नहीं माना जाएगा।

स्टार्टअप इंडिया: 80 IAC टैक्स छूट

- मान्यता प्राप्त करने के बाद कोई भी स्टार्टअप इनकम टैक्स की धारा 80 आईएसी के तहत टैक्स छूट के लिए अप्लाई कर सकता है। टैक्स छूट के लिए क्लियरेंस प्राप्त करने के बाद, स्टार्टअप निगमन की तिथि के बाद से पहले दस वर्ष से लगातार 3 वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स छूट का लाभ उठा सकता है। केवल प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ही टैक्स में छूट के लिए पात्र हैं। इसके लिए अंतर मंत्रालयी बोर्ड से प्रमाण पत्र लेना होता है।
- स्टार्टअप 1 अप्रैल, 2016 या उसके बाद शामिल किए गए स्टार्टअप इसमें आवेदन कर सकते हैं।

स्टार्टअप इंडिया पहल के उद्देश्य

नव प्रयोग, स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करने, देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहन देने के साथ ही आर्थिक विकास को गति देना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना।



सफलता की कहानी

ग्रामीण इलाकों में नया सवेरा

तमिलनाडु के श्रीधर वेम्बू को पद्म सम्मान मिला है। वह खुद एक सफल उद्यमी हैं लेकिन अब उन्होंने दूसरे उद्यमियों को निखारने का भी बीड़ा उठाया है। श्रीधर ने अपना काम ग्रामीण इलाके से शुरू किया है। वह ग्रामीण युवाओं को गांव में ही रहकर इस क्षेत्र में कुछ करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वहीं, हमारे हमारे देश में मदन पडाकी जैसे लोग भी हैं, जिन्होंने ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2014 में वन-ब्रिज नाम का मंच बनाया था। आज वन-ब्रिज दक्षिण और पूर्वी-भारत के 75 से अधिक जिलों में मौजूद है। इससे जुड़े 9,000 से अधिक ग्रामीण उद्यमी उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

मनाने की घोषणा की। इस वर्ष देश चौथा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में जब सरकार ने काम करना शुरू किया तब देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे। यह शब्द भी बमुश्किल सुनने को मिलता था लेकिन केवल 9 साल के छोटे कालखंड में भारत में स्टार्टअप की दुनिया बदल चुकी है। देश के 656 जिलों में मान्यता प्राप्त डेढ़ लाख से अधिक स्टार्टअप के साथ भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हर 8-10 दिन में एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न में बदल रहा है। देश में 118 से अधिक यूनिकॉर्न बन चुके हैं।

नई सदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल क्रांति और नए युग के इनोवेशन की सदी मानते हैं। स्टार्टअप उनकी प्राथमिकता में है। यही वजह है कि भारत की अध्यक्षता वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में भारतीय स्टार्टअप को अंतरराष्ट्रीय मंच देने के लिए एक सहभागी समूह स्टार्टअप-20 गठित किया गया है। भारत के स्टार्टअप को दुनिया भविष्य के तौर पर देख रही है। देश में पहली बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र



...ताकि आपके काम को मिले सराहना

राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार

राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार उत्कृष्ट स्टार्टअप और इको सिस्टम को सक्षम करने वालों को पहचानने और पुरस्कृत करने की एक पहल है। यह रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च क्षमता के साथ अभिनव उत्पाद या समाधान और स्केलेबल उद्यम बना रहे हैं, जो मापने योग्य सामाजिक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न ट्रैकों पर सभी फाइनलिस्टों को हैंड होल्डिंग, निवेशक संपर्क, मेंटरशिप, कॉरपोरेट संपर्क, सरकारी संपर्क, अंतरराष्ट्रीय बाजार पहुंच, विनियामक सहायता, दूरदर्शन पर स्टार्टअप चैंपियनशिप और स्टार्टअप इंडिया शोकेस जैसे सहयोग दिए जाते हैं। यह पुरस्कार 20 क्षेत्रों और विशेष श्रेणियों में दिया जाता है। अभी तक के सभी चार संस्करण में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए विशेष श्रेणी और पुरस्कार को शामिल किया गया है।

राज्यों का स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क

राज्यों का स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क प्रतिस्पर्धी संघवाद की ताकत का दोहन करने और देश में एक समृद्ध स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने की एक अनूठी पहल है। रैंकिंग अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य राज्यों को अच्छी प्रथाओं की पहचान करने, सीखने और बदलने में सुविधा प्रदान करना है। साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए राज्यों द्वारा नीतिगत हस्तक्षेप को सामने लाना है।

(इसरो) द्वारा सफलतापूर्वक निजी रॉकेट लॉन्च किया जाना भारत में स्टार्टअप की उदार नीति का प्रमाण है। भारत एक ऐसा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसका आधार स्तंभ-'ऑफ द यूथ, बाई द यूथ, फॉर द यूथ' का मंत्र हो।

युवा सपनों की उड़ान का रास्ता

महाराष्ट्र में पुणे के रहने वाले मयूर पाटिल के मन में वर्ष 2011 में अपनी मोटरसाइकिल का माइलेज बढ़ाने का ख्याल आया। मयूर की कोशिश सफल भी हुई। वर्ष 2017-18 में उन्होंने एक ऐसी तकनीक विकसित की, जिसके जरिए 40 प्रतिशत तक उत्सर्जन कम करने में सफलता मिली। वर्ष 2021 में उन्होंने इसका पेटेंट भी करा लिया। अटल न्यू इंडिया चैलेंज से 90 लाख रुपये अनुदान मिलने के बाद मयूर अब अपने चार दोस्तों के साथ खुद का स्टार्टअप चला रहे हैं।

मयूर जैसी ही कहानी अहमदाबाद के अंगद सिंह की भी है। अंगद ने माल परिवहन की वेबसाइट के साथ एक स्टार्टअप की शुरुआत की। सफलता मिली तो अंगद के कुछ दोस्त भी नौकरी छोड़कर उनके साथ जुड़ गए।

सफलता की कहानी

एस्ट्रोमी

बेंगलुरु के एक अंतरिक्ष स्टार्टअप एस्ट्रोमी की संस्थापक नेहा भी एक कमाल के आइडिया पर काम कर रही हैं। यह स्टार्टअप ऐसा फ्लैट पंटीना बना रहा है जो न केवल छोटा होगा बल्कि उसकी कीमत भी काफी कम होगी। इस तकनीक की मांग पूरी दुनिया में हो सकती है।

कुछ साल पहले यदि कोई कहता था कि वो व्यापार करना चाहता है या कोई नई कंपनी शुरू करना चाहता है तो परिवार के बड़े-बुजुर्ग, दोस्त, रिश्तेदार ऐसा करने से मना करते थे लेकिन आज यदि कोई अपनी कंपनी शुरू करना चाहता है तो उसके आसपास के सभी लोग बहुत उत्साहित होते हैं और इसमें उसका पूरा समर्थन भी करते हैं। आज यह संभव हो पा रहा है तो उसका

कारण है स्टार्टअप इंडिया।

भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य आज पूरी दुनिया देख रही है। इसी सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए देश ने स्टार्टअप ईको-सिस्टम तैयार करने की तरफ अनेक कदम उठाए हैं। शुरुआत में इस प्रयास पर भरोसा करने वाले बहुत कम थे। हमारे यहां पढ़ाई का मतलब नौकरी और नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी था। आज पूरी सोच बदल गई है। कोई बिजनेस की बात करता था- तो पहले आइडिया की नहीं, शुरुआती चिंता पैसों की रहती थी। एक धारणा बनी हुई थी कि जिसके पास पैसा है, सिर्फ वही बिजनेस कर सकता है।

स्टार्टअप ईको-सिस्टम ने उस बाधा डालने वाली सोच को तोड़ दिया है। देश के नौजवानों ने नौकरी मांगने वाले से ज्यादा नौकरी देने वाला बनने का रास्ता चुना है। आज भारत, दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इको-सिस्टम है और इनसे करीब 12-13 लाख नौजवान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। स्टार्टअप ने लगभग 12 हजार पेटेंट्स फाइल किए हैं।

इतना ही नहीं, देश ने कैसे स्टार्टअप का सहयोग किया है, उसका एक और उदाहरण है गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल। हर तरह की सरकारी खरीद-बिक्री के लिए बनाए गए इस पोर्टल पर स्टार्टअप के लिए कई विशेष सहूलियतें दी गई हैं। इन्हीं का असर है कि विभिन्न स्टार्टअप यहां 32 हजार करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर चुके हैं।

आज का युवा अब डॉक्टर-इंजीनियर के साथ-साथ एक इनोवेटर बनने का सपना, अपने स्टार्टअप को खड़ा करने का सपना भी देखने लगा है। युवाओं के पास जो प्रतिभा है या जो उसकी ट्रेनिंग है, स्टार्टअप के माध्यम से वो एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। एक तरह से कुछ वर्ष पहले देश ने पॉलिसी प्लेटफॉर्म पर जो स्टार्टअप लॉन्च किया था, वह आज सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इतना ही नहीं, 48 प्रतिशत से ज्यादा स्टार्टअप ऐसे हैं, जिनमें कम से कम एक महिला निदेशक है।

21वीं सदी में देश को आगे बढ़ाने में युवा शक्ति का महत्व है। आज भारत के छोटे-छोटे शहरों में लोग जिस तरह स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं वो अपने आप में नई पीढ़ी के लिए आकर्षण और आत्मविश्वास का केंद्र बना हुआ है। स्टार्टअप की सफलता ने युवा शक्ति के सामर्थ्य की दुनियाभर में एक पहचान खड़ी की है। स्टार्टअप से लेकर स्वरोजगार और स्पेस से ड्रोन तक, आज भारत में युवाओं

महिला उद्यमशीलता को मिल रहा बढ़ावा

भारतीय लघु उद्योग बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित कोष में 10 फीसदी इनके लिए आरक्षित है। स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम में गारंटी कवर का लाभ उठाने के लिए यूं तो वार्षिक 2 फीसदी गारंटी शुल्क का भुगतान करना होता है लेकिन पूर्वोत्तर की इकाईयों के साथ महिला उद्यमी वाली इकाईयों के लिए यह 1.5 फीसदी है।



महिला क्षमता विकास (विंग)

महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए चलाए जाने वाला कार्यक्रम है। इसमें सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों और अनुभवों को साझा करने के साथ सीख लेने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया जाता है।

स्टार्टअप इंडिया हब

स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर महिला उद्यमियों को समर्पित एक वेब पेज डिजाइन किया गया है। इस पेज पर महिला उद्यमियों के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए उपाय शामिल हैं।



स्टार्टअप कार्यशालाएं

इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्यमियों, छात्रों के लिए स्टार्टअप कार्यशालाओं की श्रृंखला आयोजित की जाती है। इसके अतिरिक्त महिला उद्यमियों पर विशेष ध्यान केंद्रित करके भी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।



सुपर स्त्री पॉडकास्ट

महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से भारतीय स्टार्टअप ईको-सिस्टम में महिलाओं पर सुपर स्त्री वीडियो पॉडकास्ट सीरिज शुरू की गई है। ये पॉडकास्ट महिला उद्यमिता को और सुदृढ़ करते हैं।



राष्ट्रपति के साथ वार्ता

18 जनवरी, 2024 को "द प्रेसिडेंट विद द पीपल" पहल के अंतर्गत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ 25 महिला उद्यमियों को वार्ता करने का अवसर मिला।

स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास और स्टार्टअप के व्यवसाय चक्र में फंड सहायता





स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS)

इन्क्यूबेटर के माध्यम से प्रारंभिक स्तर के स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देती है।

स्टार्टअप इंडिया के लिए निधियों का कोष (FFS)

उद्यम पूंजी निवेश को प्रेरित करने के लिए स्थापित किया गया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) इसका संचालन करती है जो सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि (**AIF**) को पूंजी देती है। एआईएफ बदले में स्टार्टअप में निवेश करती है।

स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (CGSS)

यह पात्र वित्तीय संस्थानों के माध्यम से डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को मॉर्टगेज फ्री लोन देने में सक्षम बनाती है। इसका संचालन राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड करती है। इसे प्रायोगिक तौर पर 1 अप्रैल, 2023 से संचालित किया गया है।



के लिए चौतरफा नए अवसरों का निर्माण हो रहा है।

केंद्र सरकार के विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन (डीआईपीपी) के अनुसार, "स्टार्टअप वह कंपनी है जो भारत में 5 वर्षों के अंदर रजिस्टर हुई है। जिसका टर्नओवर एक वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि यह कंपनी इनोवेशन, डेवलपमेंट, नए उत्पाद का व्यवसायीकरण, तकनीक आधारित सेवा या फिर बौद्धिक संपदा की दिशा में काम कर रही हो।"

विकसित भारत की भावना का प्रकटीकरण

अब बीते 10 साल में देश में जो परिवर्तन आए हैं, उन्होंने भारत के नागरिकों में जोखिम उठाने की संस्कृति को फिर से नई ऊर्जा दी है। आज देश का युवा हर क्षेत्र में जोखिम उठाने वाला बनकर उभर रहा है। वर्ष 2014 में आयुष से जुड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 3 अरब डॉलर था, जो बढ़कर लगभग 24 अरब डॉलर हो गया है। यानी, 10 साल में 8 गुना वृद्धि हुई है। इसीलिए आज देश का युवा नए-नए आयुष स्टार्टअप लॉन्च कर रहा है। पारंपरिक उत्पाद और तकनीक से जुड़े 1,250 से ज्यादा आयुष स्टार्टअप आज देश में काम कर रहे हैं। भारत अब 150 देशों में कई अरब डॉलर के आयुष उत्पाद निर्यात कर रहा है।

हर सेक्टर के उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है, इससे अलग-अलग क्षेत्र के युवाओं के लिए नए मौके बन रहे हैं। देश में भारी निवेश हो रहा है और रिकॉर्ड अवसर बन रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की पहल ने इसे नई ऊर्जा से भर दिया है। iDEX यानी Innovation for Defence Excellence जैसी स्कीम ने स्टार्टअप को गति दी है और बीते 5-6 सालों में ही भारत में करीब रक्षा उत्पादन क्षेत्र से जुड़े 1,000 नए डिफेंस स्टार्टअप बने हैं। बीते 10 वर्षों में भारत का रक्षा निर्यात 30 गुना बढ़ा है।



भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। इस युवा देश का सामर्थ्य आसमान की ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है। भारत की सोच और दृष्टिकोण में बदलाव आया है। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प भी इसी सोच को दिखाता है। स्टार्टअप जैसी क्रांति जनशक्ति से राष्ट्र शक्ति के निर्माण का सबसे बड़ा उदाहरण है। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में डिजिटल तकनीकों के इस्तेमाल पर आधारित इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए आज देश का अधिक फोकस कौशल विकास और रोजगार पर केंद्रित है। इसमें मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया जैसी पहल युवाओं की बहुत मदद कर रही हैं। मुद्रा योजना से मदद लेकर 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पहली बार कोई बिजनेस शुरु किया है। देश में आज करीब 1 लाख 54 हजार से अधिक स्टार्टअप हैं। इनमें लाखों युवा काम कर रहे हैं।

केंद्र सरकार के प्रयासों से बीते 10 वर्ष में भारत की डिजिटल इकोनॉमी, युवा शक्ति की नई ताकत और नई पहचान बनी है। भारत अग्रणी डिजिटल इकोनॉमी बन सकता है। स्टार्टअप इंडिया ने ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराए हैं। इन स्टार्टअप में भी अधिकतर को डिजिटल इंडिया का सीधा लाभ मिल रहा है।

अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप की संख्या 1 से बढ़कर 266 हो गई है। कल्पना कर सकते हैं कि कितनी अनंत संभावनाएं भारत का इंतजार कर रही हैं। इनोवेशन की यह संस्कृति विकसित भारत के निर्माण के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है। भारत ने यह विजन अपनी जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भी स्पष्ट किया है। भारत ने स्टार्टअप-20 के तहत दुनिया भर के स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक साथ लाने का प्रयास किया है। जब देश, 2047 के विकसित भारत के रोडमैप

"स्टार्टअप" के रूप में मान्यता प्रमाणपत्र, कर लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता प्रमाणपत्र, इनक्यूबेटर या फंडिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति टोल-फ्री नंबर: 18001155565 पर हब से संपर्क कर सकता है या ईमेल आईडी dipp-startups@nic.in पर संपर्क कर सकता है।



...ताकि हर संसाधन तक हो स्टार्टअप की पहुंच

स्टार्टअप इंडिया हब पोर्टल

सरकार ने 19 जून 2017 को स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन हब लॉन्च किया। यह भारत में उद्यमशीलता इकोसिस्टम के सभी स्टेकहोल्डर के लिए एक दूसरे को खोजने और जुड़ने के लिए अपनी तरह का एक ऑनलाइन मंच है। यह हब स्टार्टअप, निवेशक, फंड, सलाहकार, शैक्षणिक संस्थान, इनक्यूबेटर, एक्सेलेरेटर, कॉर्पोरेट और सरकारी निकायों सहित बहुत कुछ होस्ट करता है।

भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री (भास्कर)

भास्कर की शुरुआत सितंबर, 2024 में की गई। भास्कर सहयोग, सहकारिता में मदद करेगा और एक-दूसरे के बीच प्रतिस्पर्धा को भी सक्षम करेगा। भास्कर को संपूर्ण स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए डेटा प्रसार, आदान-प्रदान, बातचीत के लिए वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा।

नेशनल मेंटरशिप पोर्टल

देश के प्रत्येक भाग में स्टार्टअप के लिए परामर्श की पहुंच सुविधाजनक के साथ परामर्श, सहायता, लचीलापन अर वृद्धि कार्यक्रम के लिए शुरू किया गया है।



13,000

से अधिक स्टार्टअप आर्टिफिशियल इटेलीजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और नैनो टोक्नोलॉजी के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं जिनमें स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी, हरित प्रौद्योगिकी और डीपीआईआईटी के स्टार्टअप शामिल हैं।

1,250

के लगभग स्टार्टअप औषध क्षेत्र से जुड़े हैं। औषध विभाग ने फार्मा मेड-टेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवचार संवर्धन के लिए एक योजना पीआरआईपी शुरू की है।

मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में से 50 प्रतिशत से अधिक टियर-2 और टियर-3 शहरों से उभरे हैं।

880 दिन
में शुरुआती 10 हजार स्टार्टअप जुड़े थे।

100 दिन
में अगले 10 हजार से ज्यादा स्टार्टअप जुड़े।

भारतीय स्टार्टअप देश में नवाचार संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। इन स्टार्टअप ने वर्ष 2016 से मार्च 2024 तक 12 हजार से अधिक पेटेंट आवेदन किए हैं।

स्टार्टअप के लिए 135 से अधिक वैकल्पिक निवेश निधियों ने स्टार्टअप में वित्त वर्ष 2024 के अंत तक 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है।

स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत से दिसंबर, 2024 तक 62 से अधिक विनियामक सुधार किए गए ताकि स्टार्टअप को व्यवसाय करने और फंड जुटाने में आसानी हो।

भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री का उद्देश्य स्टार्टअप इकोसिस्टम में विभिन्न हितधारकों को साथ लाना है।

पर काम कर रहा है, ऐसे समय में स्टार्टअप का महत्व बढ़ जाता है। बीते दशकों में दुनिया ने देखा है कि भारत ने कैसे आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। अब भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप की संस्कृति का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है।

स्टार्टअप से यूनिकॉर्न की यात्रा

भारत सरकार युवाओं के भविष्य को आज सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आज भारत अमृत काल की बात करता है तो उसमें भारत के नौजवानों का सामर्थ्य ही प्रतिबिंबित होता है। कुछ सैकड़ा से दशक भर के भीतर ही डेढ़ लाख स्टार्टअप तक की यात्रा नौजवानों के इसी सामर्थ्य को दर्शा रही है।

युवाओं ने यूनिकॉर्न का शतक बना दिया है। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है, जिसकी कीमत 1 बिलियन डॉलर यानी 8 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी जाती है। केंद्र सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम



266
है अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप की संख्या।

2014 में सिर्फ 1 थी।

अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन केंद्र (इन-स्पेस) ने 25 से अधिक अंतरिक्ष अग्रणी और आकांक्षी देशों के साथ संबंध स्थापित किए हैं। यहां भारतीय कंपनियां अपने उत्पाद या समाधान उतार सकती हैं। इन-स्पेस ने यहां भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए तालमेल को ध्यान में रखकर 6 देशों के साथ कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप

प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना में 'नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास' कार्यक्रम नवाचार और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देता है। स्टार्टअप को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार, प्रौद्योगिकी-संचालित उच्च जोखिम और उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नैबवेंचर्स लिमिटेड के माध्यम से एग्रीटेक सहित स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए सितंबर, 2024 में एग्रीश्योर योजना आरंभ की गई है। 50 कृषि-व्यवसाय इनक्यूबेशन केंद्र बनाए गए हैं।

अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को जेनेसिस का सहयोग

जेनेसिस (इनोवेटिव स्टार्टअप के लिए जेन-नेक्स्ट सपोर्ट) : टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्टार्टअप की खोज, समर्थन, विकास और सफल बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 490 करोड़ रुपये के बजट के साथ 5 साल के लिए एक व्यापक कार्यक्रम डिजिटल इंडिया-जेनेसिस शुरू किया है।

सरकार के इन उपायों से राह आसान

- **रेगुलेटरी रिफॉर्म्स :** व्यवसाय करने, पूंजी जुटाने में सुविधा और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए अनुपालन बोझ को कम करने के लिए 2016 से सरकार ने 62 से अधिक रेगुलेटरी रिफॉर्म्स किए हैं।
- **क्रय में आसानी :** क्रय में आसानी के लिए केंद्रीय मंत्रालय और विभागों को गुणवत्ता एवं तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने वाले सभी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए पूर्व टर्नओवर-पूर्व अनुभव की शर्तों में ढील देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) स्टार्टअप से सरकार द्वारा उत्पाद और सेवाओं की खरीद को बढ़ावा दिया जाता है।
- **श्रम और पर्यावरण विधानों के तहत स्व प्रमाणन:** स्टार्टअप को निगमन की तिथि से 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए 9 श्रम और 3 पर्यावरण विधानों के तहत अपने अनुपालन को स्व प्रमाणित करने की अनुमति है।
- **स्टार्टअप के लिए तेजी से निकास :** सरकार ने स्टार्टअप को 'फास्ट ट्रैक फर्मों' के रूप से अधिसूचित किया है जिससे उन्हें अन्य कंपनियों के लिए 180 दिन की तुलना में 90 दिन के भीतर परिचालन बंद करने में सक्षम बनाय गया है।
- **बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए सहयोग:** स्टार्टअप फास्ट ट्रैक पेटेंट आवेदन परीक्षा और निपटान के लिए पात्र हैं। सरकार ने स्टार्टअप बौद्धिक संपदा संरक्षण लॉन्च किया जो स्टार्टअप को केवल वैधानिक शुल्क का भुगतान करके पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के लिए आवेदन करने की सुविधा देता है। स्टार्टअप को अन्य कंपनियें की तुलना में पेटेंट दाखिल करने में 80% की छूट और ट्रेडमार्क भरने में 50% की छूट दी जाती है।
- **भारतीय स्टार्टअप के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच** स्टार्टअप इंडिया के उद्देश्यों में भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को वैश्विक इकोसिस्टम से जोड़ना भी शामिल है। स्टार्टअप इंडिया ने करीब 21 देशों के साथ ब्रिज लॉन्च किया है जो साझेदार देशों के स्टार्टअप के लिए एक सॉफ्ट लैंडिंग प्लेटफार्म प्रदान करता है और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने में सहायता करता है।

को नीतिगत सहयोग दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं कि उनकी सरकार उन युवाओं के साथ खड़ी है जो हर चुनौती से टकराना चाहते हैं।

भविष्य के लिए देश में लाखों युवा इनोवेटर्स को तैयार करने के लिए लगातार काम हो रहा है। आज देशभर में 10



स्टार्टअप महाकुंभ

मार्च 2024 में आयोजित, स्टार्टअप महाकुंभ भारत के अब तक के सबसे बड़े स्टार्टअप कार्यक्रमों में से एक था, जिसमें रिकॉर्ड भागीदारी दर्ज की गई और नवाचार के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत किया गया। स्टार्टअप महाकुंभ से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य...

- **पारिस्थितिकी तंत्र से भागीदारी:** महाकुंभ में 48,000 से अधिक व्यावसायिक विजिटर शामिल जिसमें 1,300 से अधिक प्रदर्शक और 700 से अधिक इनक्यूबेटर रहे। 26 से अधिक राज्य, 14 से अधिक देश के प्रतिनिधिमंडल, 50 से अधिक यूनिकॉर्न और 3,800 से अधिक भावी उद्यमियों ने भाग लिया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 चुनिंदा स्टार्टअप के साथ बातचीत की और 3,000 से अधिक दर्शकों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के तहत चुने गए 120 से अधिक इनक्यूबेटरों और योजना

हजार से अधिक अटल टिंकरिंग लैब मौजूद हैं। इनमें अब 75 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और नई संभावनाओं की ट्रेनिंग दी गई है। इससे उनकी जिज्ञासाएं और बढ़ती जाती हैं और जो युवा बेहतरीन स्टार्टअप आइडिया लेकर आते हैं उनको पूरी मदद दी जाती है। एक तरह से यह स्टार्टअप नर्सरी की तरह है। यह भारत में इनोवेशन की नई लहर पैदा करेगी।

आज स्टार्टअप की दुनिया नए भारत की भावना को प्रकट कर रही है। जब भारत ने यूनिकॉर्न में शतक लगाया था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2022 के मन की बात कार्यक्रम में कहा था, "इस महीने 5 तारीख को देश में यूनीकॉर्न की संख्या 100 के आंकड़े तक पहुंच गई है और आपको तो पता ही है, एक यूनीकॉर्न यानी, कम-से-कम साढ़े सात हजार करोड़ रुपये का स्टार्टअप। इन यूनिकॉर्न का कुल मूल्यांकन 330 बिलियन डॉलर, यानी 25

द्वारा समर्थित 350 से अधिक स्टार्टअप ने दुनिया के सामने भारत के जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित किया। पीएम मोदी से जिन 6 स्टार्टअप संचालकों को बातचीत का मौका मिला उनमें से 4 सीड-फंडेड स्टार्टअप थे।

- **SCO स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण:** **SCO** स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण स्टार्टअप महाकुंभ के दौरान आयोजित किया गया जिसमें 8 देश के 35 से अधिक प्रतिनिधि हाइब्रिड प्रारूप में शामिल हुए। **SCO** पैवेलियन में 15 से अधिक **SCO** स्टार्टअप ने अपने उत्पाद और सेवाएं प्रदर्शित कीं।

विषयगत मंडप-स्टार्टअप शोकेस



स्टार्टअप के सबसे बड़े शोकेस में से एक, जिसमें स्टार्टअप इंडिया, **DPIIT** द्वारा मान्यता प्राप्त 800 स्टार्टअप शामिल हुए। एग्रीटेक पैवेलियन, **AI** और **SaaS** पैवेलियन ने **AI** फॉर पब्लिक गुड प्रतियोगिता को प्रदर्शित किया।

- **उद्यमिता के भविष्य को आगे बढ़ाना:** 22 राज्यों के 3,000 से अधिक उद्यमिता छात्रों ने संस्थापकों, पैनल चर्चाओं और मास्टर क्लास के साथ सत्रों में भाग लिया। तीन दिन में 160 से अधिक सत्र आयोजित किए गए।
- स्टार्टअप महाकुंभ का अगला संस्करण अप्रैल 2025 में आयोजित किया जाएगा, जिसमें इस बार वैश्विक स्तर पर और भी अधिक उपस्थिति होगी।

पूर्वोत्तर में स्टार्टअप को बढ़ावा देता ASCEND

स्टार्टअप इंडिया ने एक्सीलरेटिंग स्टार्टअप कैलिबर एंड एंटरप्रिन्योरियल ड्राइव(**ASCEND**) कार्यक्रम की शुरुआत पूर्वोत्तर भारत में उद्यमी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया। 2022, 2023 और 2024 में इस पहल में उद्यमी, महत्वाकांक्षी उद्यमी और छात्रों के लिए भौतिक और आभासी क्षमता निर्माण सत्र आयोजित किए गए। **ASCEND** के तहत वित्तीय साक्षरता बूटकैंप शामिल हैं जिसमें सात राज्यों में 850 से अधिक प्रतिभागियों को 3,400 से अधिक मेंटरशिप घंटे दिए गए। कार्यशाला और आभासी सत्रों के माध्यम से छह पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिभागियों को शामिल किया गया। **ASCEND** के तहत ही **MAARG** मेंटरशिप प्रोग्राम में मार्केटिंग और व्यावसायिक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मास्टरक्लास और वन-ऑन-वन सत्रों के माध्यम से 190 घंटे से अधिक की मेंटरशिप प्रदान की। **ASCEND** स्टार्टअप वेबिनार में **DPIIT** मान्यता, कर छूट, सीड फंडिंग, बौद्धिक संपदा अधिकार और सरकारी प्लेटफॉर्म जैसे विषयों पर आवश्यक जानकारी प्रसारित करने के लिए 300 घंटे से अधिक की मेंटरशिप प्रदान किए गए। जिसने पूर्वोत्तर राज्यों में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने, स्थानीय प्रतिभाओं को सशक्त बनाने और नवाचार-संचालित विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। निश्चित रूप से यह बात हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात है। एक अच्छी बात यह भी है कि हमारे यूनिकॉर्न विविधता से भरे हैं। यह ई-कॉमर्स, फिनटेक, एडुटेक, बायोटेक जैसे कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। एक और बात जिसे मैं ज्यादा अहम मानता हूं वो यह है कि स्टार्टअप की दुनिया नए भारत की भावना को परिलक्षित कर रही है।"

निश्चित रूप से भारत की विकास यात्रा, भारत की सफलता की कहानी अब अमृत काल में एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी। अमृत काल में विकसित भारत की मजबूत नींव से नए भारत का भविष्य तय होगा, देश की दिशा तय होगी। भारत की स्टार्टअप क्रांति इस अमृत काल की बहुत महत्वपूर्ण पहचान बनेगी। स्टार्टअप और युवाओं की आकांक्षा ही भारत की आकांक्षा है। भारत अब जब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है तब उसमें उसमें स्टार्टअप की बड़ी भूमिका होगी। ●



केन-बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना

बुंदेलखंड क्षेत्र में खुशहाली और समृद्धि की नई राह

भारत जैसे भौगोलिक रूप से विविधता भरे देश में जहां एक ही समय कोई हिस्सा अतिवृष्टि तो कोई सूखे से लड़ रहा होता है... 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सपना देखा... नदियों को जोड़ने का। 22 वर्ष बाद 25 दिसंबर को बुंदेलखंड की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाजपेयी के इसी सपने को उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर धरातल पर उतार दी उन्हें श्रद्धांजलि...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना की नींव रखी। यह परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी के 22 साल पहले देखे उस सपने को पूरा करने की शुरुआत है, जिसके माध्यम से उन्होंने वर्षों से बूंद-बूंद को तरस रहे बुंदेलखंड की प्यास को तृप्त करने का संकल्प लिया था। इस संकल्प की शुरुआत हुई थी 2002 में। तब देश का बड़ा हिस्सा भयानक सूखे का सामना कर रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों को आपस में जोड़ने के काम की व्यावहारिकता परखने के लिए एक कार्य दल का गठन किया। इसने इसी साल अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी। नदी जोड़ो योजना में गंगा सहित 60 नदियों को जोड़ने की योजना थी। मकसद था कि इससे कृषि योग्य लाखों हेक्टेयर भूमि की मॉनसून पर निर्भरता कम हो जाएगी। करीब 12 साल तक तक नदी जोड़ो की यह अवधारणा बस फाइलों में ही कैद हो कर रह गई। प्रधानमंत्री बनने से पहले अप्रैल, 2014 में बिहार में आयोजित एक रैली के बाद नरेंद्र मोदी ट्वीट कर कहा था, 'नदियों को जोड़ने का अटलजी का सपना ही हमारा भी सपना है। हमारे मेहनती किसानों को यह ताकत दे सकता है।' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए एक विशेष समिति का गठन भी किया। अप्रैल, 2015 में एक विशेष कार्यबल भी गठित किया गया।

केन-बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र में खुशहाली और समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। 44,600 करोड़ रुपये

आज सात दशक बाद भी देश के अनेक राज्यों के बीच पानी को लेकर कुछ न कुछ विवाद है। पिछली सरकारों ने इसे सुलझाने के लिए सही नीयत से कभी भी ठोस प्रयास नहीं किए। जल संकट के स्थायी समाधान के लिए सोचा ही नहीं गया। जब देश में अटलजी की सरकार बनी, तब उन्होंने पानी से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए गंभीरता से काम शुरू किया था।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

22 मार्च, 2021 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर

39,317 करोड़ रुपये
की केंद्रीय सहायता को परियोजना के लिए मंजूरी दी है।

36,290 करोड़ रुपये का अनुदान	3,027 करोड़ रुपये का लोन

की लागत से बनने वाली इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों के जीवन में सुधार आएगा। पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से बुंदेलखंड के लोगों को पिछली सरकारों के कुशासन के कारण दशकों तक कष्ट सहना पड़ा। बुंदेलखंड में किसान और महिलाओं की कई पीढ़ी को प्रभावी शासन की कमी के कारण पानी की एक-एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ा। पूर्ववर्ती सरकारों ने जल संकट के स्थायी समाधान के बारे में नहीं सोचा। डॉ. भीमराव अंबेडकर भारत के लिए नदी जल के महत्व को समझने वाले पहले लोगों में से एक थे। भारत में प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं डॉ. अंबेडकर के विजन पर



103
मेगावाट जल एवं 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का होगा उत्पादन

एमपी-यूपी के 65 लाख लोगों को सीधा लाभ

मध्य प्रदेश– छतरपुर | दमोह | सागररायसेन | विदिशा | टीकमगढ़ | पन्ना | शिवपुरी | निवाड़ी | दतिया |

उत्तर प्रदेश– बांदा | महोबा | झांसी | ललितपुर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2020-21 की कीमतों के आधार पर 44,605 करोड़ रुपये की कुल लागत को दी मंजूरी।



राज्यों को लाभ

	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश
सिंचाई	8.11 लाख हेक्टेयर	2.51 लाख हेक्टेयर
पेयजल	2,000 गांव 44 लाख आबादी	21 लाख आबादी

77 मीटर ऊंचा | 2.12 किमी लंबा

2,853 मिलियन घन मीटर क्षमता

छतरपुर जिले की बिजावर तहसील में पन्ना टाइगर रिजर्व के दौधन गांव के पास बनेगा बांध

मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश में लिंक मार्ग में आने वाले पुराने तालाबों की मरम्मत के बाद उनमें पानी भरा जाएगा



इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने किया बाबा साहब को याद

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने रखी थी जल संसाधन की नींव

डॉ. अंबेडकर ने 1942-46 के दौरान देश के जल संसाधनों के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए एक नई जल और बिजली नीति विकसित की। डॉ. अंबेडकर कहते थे कि केवल बहुउद्देशीय परियोजना ही नदी के नियंत्रण के लिए एक अच्छी संभावना हो सकती है, जिससे बाढ़ नियंत्रण, बारहमासी सिंचाई और बिजली की जरूरी आपूर्ति की जा सकती है। उनका दृष्टिकोण था कि अतिरिक्त पानी कोई खतरा नहीं है। इसका विनाश नहीं होता है। इसे संरक्षित किया जा सकता है। इसी विचार से बहुउद्देश्यीय जल संसाधन विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई। दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं और हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजनाएं डॉक्टर अंबेडकर की देन कही जाती हैं। राज्यों के बीच जल विवाद को निपटाने के लिए बने कानून अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 और नदी बोर्ड अधिनियम भी डॉ. अंबेडकर की ही देन माने जाते हैं।



उपलब्धियों का जिक्र... कोशिशों से मुकाम तक

- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने जल से जुड़ी जिम्मेदारियों को अलग-अलग विभागों में बांट दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने एकीकृत जल शक्ति मंत्रालय बनाया।
- आजादी के बाद के सात दशकों में केवल 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल कनेक्शन, लेकिन पिछले पांच वर्ष में 12 करोड़ नए परिवारों को नल से पानी उपलब्ध कराया गया है। योजना पर 3.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं।
- 2014 से पहले देश में करीब 100 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं थीं, जो दशकों से अधूरी थीं। केंद्र सरकार ने पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपये खर्च किए और आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग बढ़ाया है।
- आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया। देशभर में 60,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए हैं।

आधारित थीं और केंद्रीय जल आयोग की स्थापना भी उनके प्रयासों के कारण ही हुई थी। पिछली सरकारों ने जल संरक्षण एवं बड़ी बांध परियोजनाओं में उनके योगदान के लिए डॉ. अंबेडकर को कभी उचित श्रेय नहीं दिया, इन प्रयासों के प्रति वह कभी गंभीर नहीं रहीं। सात दशक बाद भी भारत के कई राज्यों में अभी भी जल विवाद है, पिछली सरकारों की गलत नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं।

केन-बेतवा जोड़ो परियोजना एक वास्तविकता बनने वाली है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली के नए द्वार खोलेगी। पीएम मोदी ने कहा, "नदियों को जोड़ने के विशाल अभियान के तहत दो परियोजनाओं की शुरुआत करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है।" जल सुरक्षा 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। वही देश और क्षेत्र प्रगति करेगा, जिसके पास पर्याप्त जल होगा क्योंकि समृद्ध खेतों और संपन्न उद्योगों के लिए जल आवश्यक है।



दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर प्लांट की शुरुआत...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खंडवा के ओंकारेश्वर में दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर प्लांट का भी उद्घाटन किया। इसके पहले फेज में 6 लाख सोलर प्लेट से 278 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है। दूसरे फेज में 240 मेगावाट बिजली का और उत्पादन होगा। 12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस प्लांट को तीन खंडों में बनाया गया है, इसके साथ 300 मेगावाट क्षमता का एक विद्युत सब स्टेशन भी बनाया गया है। ●





प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का मार्ग बताती हैं
प्रभु ईसा मसीह की शिक्षाएं

दुनियाभर के लोग हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। ईसाई समुदाय का यह सबसे बड़ा त्योहार सिर्फ उत्सवभर ही नहीं, बल्कि शांति बिना अस्तित्व नहीं और सबको साथ लेकर चलने के यीशु के सिद्धांत से प्रेरणा लेने का भी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के क्रिसमस समारोह में प्रभु यीशु के दिखाए कल्याण के रास्ते का किया जिक्र...

बाइबल कहती है- Carry each other's burdens यानी, हम एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे के कल्याण की भावना रखें। बाइबल की इसी सोच के साथ राष्ट्र के संस्थान और संगठन, समाज सेवा में बड़ी भूमिका निभाते हैं। नई दिल्ली में आयोजित क्रिसमस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में नए स्कूलों की स्थापना हो ताकि हर वर्ग और हर समाज को आगे बढ़ाया जा सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों की सेवा के संकल्प को हम सब अपनी जिम्मेदारी मानते हैं।

भारत विदेश नीति में राष्ट्रीय हित के साथ-साथ मानव हित को प्राथमिकता देता है। कोरोना के समय पूरी दुनिया ने इसे देखा और महसूस किया। भारत ने परमार्थ भाव से सामर्थ्य से भी आगे जाकर कितने ही देशों की मदद की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में दवाइयां पहुंचाईं, कई देशों को वैक्सीन भेजी। इसका दुनिया पर बहुत सकारात्मक असर भी पड़ा। भारत की यह भावना, मानवता के लिए समर्पण, मानव केंद्रित प्रतिबद्धता ही 21वीं सदी की दुनिया को नई ऊंचाई पर ले जाएगी।

कार्यक्रम में पीएम मोदी ने ईसाई समुदाय के प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत की जिसमें कार्डिनल, बिशप और चर्च से जुड़े लोग शामिल थे। यह पहला मौका था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कैथोलिक चर्च मुख्यालय के कार्यक्रम में भाग लिया। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की स्थापना 1944 में हुई थी जो भारत में सभी कैथोलिकों के साथ मिलकर काम करती है। पिछली बार पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री निवास पर ईसाई समुदाय के लोगों के साथ क्रिसमस मनाया था। इस कार्यक्रम से पूर्व प्रधानमंत्री मोदी 19 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के निवास पर क्रिसमस समारोह में शामिल हुए और ईसाई समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्यों के साथ बातचीत की थी। ●

> "मुझे विश्वास है, हम सबके सामूहिक प्रयास हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। विकसित भारत, हम सभी का लक्ष्य है और हमें इसे मिलकर पाना है। यह आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम उन्हें एक उज्ज्वल भारत देकर जाएं।
>
> – नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

राजस्थान की चमक और विकास का उत्सव



पिछले एक वर्ष में राज्य में रखी गई विकास की नींव ने राजस्थान के लोगों को विकास का उत्सव मनाने का मौका दिया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर को राजस्थान सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर जयपुर में आयोजित कार्यक्रम 'एक वर्ष-परिणाम उत्कर्ष' में हिस्सा लेने के साथ ही 46,300 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास...

विकसित भारत की राह को आसान बनाने के लिए राजस्थान में सड़क, रेल, बिजली, जल संसाधन और संरक्षण सहित अन्य दूसरी आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार राज्य को हर संभव मदद दे रही है। राज्य में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं को देखते हुए बड़े स्तर पर कार्य किया जा रहा है, इससे देश में राज्य की एक अलग पहचान बनेगी। 2014 से पहले के दशक से तुलना करें तो पिछले एक दशक में राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में दोगुने से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक वर्ष-परिणाम उत्कर्ष' कार्यक्रम में कहा, "आज केंद्र और राज्य की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन रही हैं।" राजस्थान में सौर ऊर्जा की काफी संभावनाएं हैं और यह इस क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन सकता है। सरकार ने सौर ऊर्जा को बिजली बिल शून्य करने का साधन बनाया है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित-पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से राजस्थान को बहुत लाभ होगा। इस योजना के तहत केंद सरकार छत पर सौर पैनल लगाने के लिए 78,000 रुपये प्रदान करती है। इस योजना के लिए 1.4 करोड़ से अधिक परिवारों ने अभी तक पंजीकरण

इन परियोजनाओं का हुआ उद्घाटन और शिलान्यास

उद्घाटन

11,000 करोड़ रुपये

से अधिक की नौ परियोजना, जिनमें केंद्र सरकार की सात और राज्य सरकार की दो परियोजना शामिल है।

- नवनेरा बैराज, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क और परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली से जुड़ी परियोजनाएं, रेलवे के भीलड़ी-समदड़ी-लूणी-जोधपुर-मेड़ता रोड-डेगाना-रतनगढ़ खंड का विद्युतीकरण और दिल्ली-वडोदरा ग्रीन फील्ड एलाइनमेंट (एनएच-148 एन) (एसएच-37ए के जंक्शन तक मेज नदी पर प्रमुख पुल) परियोजना।

शिलान्यास

35,300 करोड़ रुपये

से अधिक की 15 परियोजना, जिनमें केंद्र सरकार की नौ और राज्य सरकार की 6 परियोजना शामिल है।

- 9,400 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से रामगढ़ बैराज और महलपुर बैराज के निर्माण कार्य तथा चंबल नदी पर नहर के माध्यम से नवनेरा बैराज से बीसलपुर बांध और ईसरदा बांध तक पानी स्थानांतरित करने की प्रणाली।
- सरकारी कार्यालय भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने, पूगल (बीकानेर) में 2,000 मेगावाट के एक सौर पार्क और 1,000 मेगावाट के दो चरणों के सौर पार्कों के विकास तथा सैपऊ (धौलपुर) से भरतपुर-डीग-कुम्हेर-नगर-कामाण और पहाड़ी तथा चंबल-धौलपुर-भरतपुर तक पेयजल आपूर्ति लाइन के रेट्रोफिटिंग कार्य।
- लूणी-समदड़ी-भीलड़ी डबल लाइन, अजमेर-चंदेरिया डबल लाइन और जयपुर-सवाई माधोपुर डबल लाइन रेलवे परियोजना के साथ-साथ अन्य ऊर्जा पारेषण से संबंधित परियोजना।



प्रमुख बाजार और वैष्णो देवी मंदिर से जुड़ेगा राजस्थान

मेज नदी पर पुल के निर्माण से सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक और कोटा जिलों को लाभ होगा, जिससे इन जिलों के किसानों के लिए दिल्ली, मुंबई और वडोदरा के प्रमुख बाजारों तक पहुंच आसान हो जाएगी। जयपुर और रणथंभौर टाइगर रिजर्व तक पर्यटकों की पहुंच भी आसान होगी। जामनगर-अमृतसर आर्थिक गलियारा, जब दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा, तो राजस्थान वैष्णो देवी मंदिर से जुड़ जाएगा। इससे उत्तर भारत के उद्योगों को कांडला और मुंद्रा बंदरगाहों तक सीधी पहुंच मिलेगी, जिससे राजस्थान में परिवहन क्षेत्र को बड़े गोदामों की स्थापना से लाभ होगा।

कराया है। लगभग 7 लाख घरों में पहले ही सौर पैनल प्रणाली स्थापित हो चुकी है। राजस्थान में 20,000 से अधिक घर इस पहल में शामिल हैं। इन घरों ने सौर ऊर्जा का उत्पादन शुरू कर दिया है जिससे उनके बिजली बिलों में कमी हो रही है।

राजस्थान में 45,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास से पानी के क्षेत्र में आ रही बाधाओं का उचित समाधान, राजस्थान को सबसे बेहतर संपर्क वाले राज्य, निवेशकों को आकर्षित करने में मदद, रोजगार के अवसर, पर्यटन क्षेत्र में मजबूती, किसानों, महिलाओं तथा युवाओं को लाभ होगा। राजस्थान सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में किए गए कार्य और परियोजनाओं से गरीब परिवार, महिला, मजदूर, विश्वकर्मा और घुमंतू जनजाति के विकास के लिए कई फैसले लिए गए हैं। राजस्थान की मौजूदा सरकार ने पिछले एक साल में रोजगार के हजारों अवसर भी पैदा किए हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में नई सरकार बनते ही पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना पर एक समझौता हुआ। इसके तहत चंबल नदी और उसकी सहायक पार्वती, कालीसिंध, कुनो, बनास, रूपारेल, गंभीरी और मेज जैसी नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। जल्द ही ऐसा समय आने वाला है, जब राजस्थान को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा और विकास के लिए पर्याप्त पानी होगा। पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना से राजस्थान के 21 जिलों को सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध होगा। ●



10,000 से अधिक M-PACS, डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ



डिजिटलाइजेशन से पारदर्शी पैक्स

सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने न सिर्फ अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया बल्कि डिजिटलाइजेशन के जरिए पारदर्शी और रोजगारपरक बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए। इसका परिणाम हुआ कि कुछ वर्ष में ही देश में सहकारिता का दायरा बढ़ा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 25 दिसंबर को 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समिति (एम-पैक्स), डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियों की शुरुआत की...

केंद्र सरकार ने जब वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया तब 'सहकार से समृद्धि' का विजन दिया था। 'सहकार से समृद्धि' तभी संभव है, जब हर पंचायत में सहकारिता की उपस्थिति हो और वहां यह किसी न किसी रूप में काम करे, क्योंकि देश के त्रिस्तरीय सहकारिता ढांचे को सबसे ज्यादा ताकत प्राथमिक सहकारी समिति ही दे सकती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 2 लाख नए पैक्स बनाने का निर्णय लिया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि 19 सितंबर 2024 को एक SOP बनाई गई और उसके 86 दिन के अंदर ही 10 हजार पैक्स को पंजीकृत करने का काम पूरा कर लिया गया है। नाबार्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड (एनएफडीबी) ने 10 हजार प्राथमिक सहकारी समितियों के पंजीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।

सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद सबसे बड़ा काम सभी पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन करने का किया गया। कम्प्यूटराइजेशन के आधार पर पैक्स को 32 प्रकार की नई गतिविधियों से जोड़ा गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि पैक्स को बहुआयामी बनाकर



कंप्यूटराइजेशन और टेक्नोलॉजी से पैक्स में पारदर्शिता आएगी। सहकारिता का जमीनी स्तर पर विस्तार होगा। यह महिला एवं युवाओं के रोजगार का माध्यम भी बनेगा। पैक्स, कृषि संसाधनों की सरल उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा।

– अमित शाह, **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

अगले पांच साल में 2 लाख नए पैक्स का गठन करेगी केंद्र सरकार

- केंद्र सरकार ने 5 साल में 2 लाख नए पैक्स के गठन का लक्ष्य रखा है। इससे किसानों की उपज को वैश्विक बाजार में पहुंचाना सरल हो जाएगा।

22,750 पैक्स पहले चरण में नाबार्ड बनाएगा।

47,250 पैक्स दूसरे चरण में नाबार्ड बनाएगा।

इसी प्रकार एनडीडीबी 56,500 नई समितियां बनाएगा और 46,500 मौजूदा समितियों को सुदृढ़ बनाएगा।

- एनएफडीबी 6,000 नई मत्स्य सहकारी समितियां बनाएगा और 5,500 मौजूदा मत्स्य सहकारी समितियों का सशक्तीकरण करेगा। इसके अलावा राज्यों के सहकारी विभाग 25,000 पैक्स बनाएंगे।
- नए मॉडल बायलॉज के साथ अब तक 11,695 नई प्राथमिक सहकारी समितियां पंजीकृत हुई हैं जो बड़ी उपलब्धि है।

हर पंचायत में सहकारी समितियों की स्थापना को प्रतिबद्ध सहकारिता मंत्रालय

नए एम-पैक्स के गठन से ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता से जुड़ी संस्थाओं के विकास को बढ़ावा मिलेगा। नवनिर्मित बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी सहकारी और मत्स्य सहकारी समितियों में ऋण वितरक संस्था, डेयरी समितियां और मत्स्य पालन समितियां शामिल हैं। नवनिर्मित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (एम-पैक्स) से ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

और उन्हें भंडारण, खाद, गैस, उर्वरक और जल वितरण के साथ जोड़ा। ट्रेंड मैनपावर न होने के कारण यह सब नहीं हो पा रहा था लिहाजा अब प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी शुभारंभ हुआ है जो पैक्स के सदस्य और कर्मचारियों को संपूर्ण प्रशिक्षण देने का काम करेंगे।

कार्यक्रम के दौरान 10 सहकारी समितियों को रूपे किसान क्रेडिट कार्ड, माइक्रो एटीएम का वितरण किया गया। अभियान के तहत आने वाले दिनों में हर प्राथमिक डेयरी को माइक्रो एटीएम दिया जाएगा। माइक्रो एटीएम और रूपे किसान क्रेडिट कार्ड हर किसान को कम खर्च पर ऋण देने का काम करेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि पैक्स के विस्तार के लिए इसमें 32 कामों को जोड़कर विजिबल और वायबल बनाया है। गांव में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) जब पैक्स बन जाता है तो गांव के हर नागरिक को किसी न किसी रूप में पैक्स के दायरे में आना पड़ता है, इस प्रकार इसकी उपयोगिता बढ़ाई गई है। जब पैक्स गैस वितरण, भंडारण, पेट्रोल वितरण आदि का काम करते हैं तो उनकी स्वीकार्यता अपने आप बढ़ जाती है। पैक्स के माध्यम से किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ●

देश छू रहा नई ऊंचाइयां
नए अवसरों का हो रहा निर्माण

किसी भी देश का विकास वहां के युवाओं की कड़ी मेहनत, क्षमता और उसके नेतृत्व पर निर्भर करता है। इसीलिए वर्ष 2047 तक विकसित होने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे भारत की नीति और निर्णय अपने युवाओं को सशक्त करने पर केंद्रित हैं। युवाओं की सशक्तीकरण की इसी राह पर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 दिसंबर को रोजगार मेले के माध्यम से नवनियुक्त 71,000 से अधिक लोगों को वितरित किए नियुक्ति पत्र...

रोजगार मेला प्रधानमंत्री की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। यह युवाओं को राष्ट्र निर्माण और सशक्तीकरण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करता है। इतना ही नहीं, पिछले एक दशक में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी हर योजनाए खासतौर पर युवाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई हैं। आज भारत का युवा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो हर सेक्टर में अपना परचम लहरा रहा है। रोजगार मेले में नवनियुक्त लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर प्राकृतिक खेती तक, अंतिरक्ष से रक्षा क्षेत्र तक, पर्यटन से स्वास्थ्य तक हर सेक्टर में अब देश नई ऊंचाइयां छू रहा है।

देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा प्रतिभा को निखारने की जरूरत होती है और शिक्षा व्यवस्था पर यह जिम्मेदारी है। नए भारत के निर्माण के लिए देश दशकों से एक आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की जरूरत महसूस कर रहा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश अब उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले ग्रामीण, दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के युवाओं के लिए भाषा बहुत बड़ी दीवार बन जाती थी। केंद्र की सरकार ने



करीब डेढ़ साल में 10 लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरी



पिछले 10 वर्ष से सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। पिछले करीब डेढ़ साल में ही लगभग 10 लाख युवाओं को केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरी दी है। यह अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। पूर्व में इस तरह मिशन मोड में युवाओं को भारत सरकार में पक्की नौकरी नहीं मिली है। आज देश में न केवल लाखों युवा को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं बल्कि ये नौकरियां पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दी जा रही हैं। इस पारदर्शी परंपरा से आए युवा भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा में जुट रहे हैं।



"युवा इस देश की ताकत हैं। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं, जिसे हमारे युवा हासिल न कर सकें। युवाओं को अब नई ऊर्जा के साथ नई शुरुआत करनी है। आपको उज्ज्वल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।"

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

मातृभाषा में पढ़ाई और परीक्षा की नीति बनाई। अब युवाओं को 13 भाषा में भर्ती परीक्षाएं देने का अवसर मिला। बॉर्डर जिले के युवाओं को ज्यादा मौका देने के लिए उनका कोटा बढ़ाया गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए विशेष भर्ती रैलियां की जा रही हैं।

केंद्र सरकार का प्रयास है कि हर क्षेत्र में महिलाएं आत्मनिर्भर बनें। यही वजह है कि सरकार ने 30 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते खोले, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा फायदा मिलने लगा। मुद्रा योजना से महिलाओं को बिना गारंटी लोन मिला तो पोषण अभियान, सुरक्षित मातृत्व अभियान और आयुष्मान भारत के माध्यम से महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है।

विभिन्न स्तरों पर काम करेंगे नवनियुक्त कर्मचारी

रोजगार मेला प्रधानमंत्री की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है। यह युवाओं को राष्ट्र निर्माण और आत्म सशक्तीकरण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करता है। देशभर में चयनित 45 स्थल पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। नियुक्ति पत्र पाने वाले यह नए कर्मचारी गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग सहित विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में काम करेंगे।

आईगॉट पर 1,600 से ज्यादा पाठ्यक्रम उपलब्ध

सरकारी कार्यालय और कामकाज को लेकर एक पुरानी छवि थी जिसमें 10 वर्ष में बड़ा बदलाव आया है। अब सरकारी कर्मचारियों में ज्यादा दक्षता और उत्पादकता दिख रही है। कर्मचारियों को सीखते रहने में आईगॉट कर्मयोगी से बहुत मदद मिल रही है। आईगॉट पर 1,600 से ज्यादा अलग-अलग प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं। इसके माध्यम से कर्मचारी बहुत कम समय में, प्रभावी तरीके से विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं। ●



जीवन को ऊंचाई देने में बेटी-बेटे बनें सपने के दो पंख

‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ की एक दशक में ऊंची उड़ान

बेटियां ईश्वर का अनमोल उपहार हैं, लेकिन पहले देश में इन्हें कमतर आंका जाता था। 1961 से 2011 तक हर जनगणना में बेटियों की संख्या बेटों से कम रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भिक्षुक बनकर बेटियों की जिंदगी की भीख मांगने के साथ जिस बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पहल की शुरुआत की थी, इस वर्ष 22 जनवरी को वह अभियान एक दशक पूरा कर रहा है। राष्ट्रीय बालिक दिवस 24 जनवरी के मौके पर आइए जानते हैं कैसे इसने लोगों की मानसिकता के साथ व्यवस्थाओं को बदला...

> “देश का प्रधानमंत्री एक भिक्षुक बनकर आपसे बेटियों की जिंदगी की भीख मांग रहा है। बेटियों को अपने परिवार का गर्व मानें, राष्ट्र का सम्मान मानें। आप देखिए इस असंतुलन में से हम बहुत तेजी से बाहर आ सकते हैं। बेटा और बेटी दोनों वो पंख है जीवन की ऊंचाईयों को पाने का उसके बिना कोई संभावना नहीं। ऊंची उड़ान भी भरनी है तो सपनों को बेटे और बेटी दोनों पंख चाहिए तभी तो सपने पूरे होंगे।”

हरियाणा में पानीपत की धरती से 22 जनवरी, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी अपील के साथ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया था। उसके बाद कई अवसरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “हमारा मंत्र होना चाहिए; ‘बेटा-बेटी एक समान’। वहीं, पीएम मोदी ने वाराणसी में अपने गोद लिए गए गांव जयापुर में नागरिकों से कहा



...ताकि पढ़ें बेटियां, बढ़ें बेटियां

यह योजना गिरते बाल लिंग अनुपात और जीवन-चक्र निरंतरता में महिला सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए शुरू की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य...

- लिंग आधारित जन्म चयन पर रोकथाम।
- बालिकाओं के अस्तित्व एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
- बालिका के लिए शिक्षा एवं रोजगार की उचित व्यवस्था और भागीदारी सुनिश्चित करना।
- बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना।

था, "आइए कन्या के जन्म का उत्सव मनाएं। अपनी बेटी के जन्मोत्सव पर आप पांच पेड़ लगाएं।" इसी तरह हरियाणा के बीबीपुर के सरपंच की 'Selfie With Daughter' पहल के लिए न सिर्फ प्रशंसा की बल्कि मन की बात कार्यक्रम में बेटियों के साथ सेल्फी भेजने का अनुरोध किया, जिसे वैश्विक स्तर पर सराहा गया। ऐसी ही अपील, आह्वान और सरकारी तंत्र में लड़कियों के लिए खोले गए अवसर के द्वार ने समाज में लड़कियों को लेकर मानिसकता बदली है। आंकड़े बता रहे हैं कि वो पढ़ भी रही हैं और बढ़ भी रही हैं।

समाज की मानसिकता बदलने और सशक्तीकरण में बनी सहायक

4 करोड़ से अधिक पहुंची सुकन्या समृद्धि खातों की संख्या।

करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि जमा। चालू वित्त वर्ष में जमा राशि पर ब्याज 8.2% है।

- 3,00,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि 2024-25 के बजट में महिला उन्मुखी विकास को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने आवंटित की है।

33%

सीटें आरक्षित की गईं महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 से लोकसभा और एनसीटी दिल्ली सहित राज्यों की विधानसभा में।

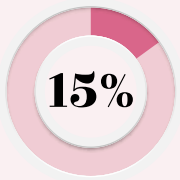


सैनिक स्कूल और नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में लड़कियों के प्रवेश का दरवाजा खोला गया।

- 100 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी या 300 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाली प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति को अनिवार्य किया गया है।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम में महिला उद्यमियों को वार्षिक गारंटी शुल्क में 10 फीसदी की छूट और 10 फीसदी अतिरिक्त गारंटी कवरेज की व्यवस्था।
- स्टैंडअप इंडिया योजना में हर बैंक को कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये के बीच लोन देने का लक्ष्य तय किया गया है।
- सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और मजदूरी संहिता 2019 में क्रमशः महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ और लिंग के आधार पर भेदभाव न करने के संबंध में प्रावधान है।
- मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 में 50 या अधिक कर्मचारी वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान में क्रेच की सुविधा की अनिवार्यता के साथ मातृत्व अवकाश 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है।
- कामकाजी माता को उनके बच्चों की उचित देखभाल के लिए डे केयर सुविधाएं एवं सुरक्षा के लिए 1 अप्रैल 2022 से 'पालना' योजना शुरू की गई है।

जमीं से आसमां तक बेटियों का राज





हैं भारत में महिला पायलट जो विश्व में सर्वाधिक

40.3%

हो गया 15 वर्ष और उससे अधिक के लिए रोजगार का प्रतिशत, जो अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017-18 में 22 फीसदी था।



6 करोड़

से अधिक महिलाएं देश में कृषि मजदूर के रूप में कार्यरत हैं।

10.05 लाख परिवारों के सदस्य दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में शामिल जो देश में ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव ला रहे हैं।

25,385

महिला कल्याण सहकारी समिति नवंबर, 2024 तक हैं पंजीकृत।

- 84% लोन स्टैंडअप इंडिया में महिलाओं को उपलब्ध कराए गए। स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने के लिए 2023-24 से 2025-26 तक के लिए 'नमो ड्रोन दीदी' योजना को मंजूरी दी गई है जिसमें 15 हजार ड्रोन दिए जाने हैं।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के कुल लाभार्थियों में से 39 फीसदी महिलाएं हैं।
- 75.46 फीसदी है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के कुल नामांकन में महिला कारीगरों का नामांकन। 75,000 स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक हैं।
- देश में आम चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की संख्या 1957 में 3 फीसदी थी जो 2024 में बढ़कर 10 फीसदी हुई। निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या पहली लोकसभा में 22 थी जो 18वीं लोकसभा में 75 हुई।
- 14.50 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं पंचायती राज संस्थाओं में। आरक्षित सीटें 33 फीसदी हैं लेकिन इनकी संख्या 46 फीसदी पहुंच गई है।

सशक्तीकरण बजट नहीं बाधा

128%

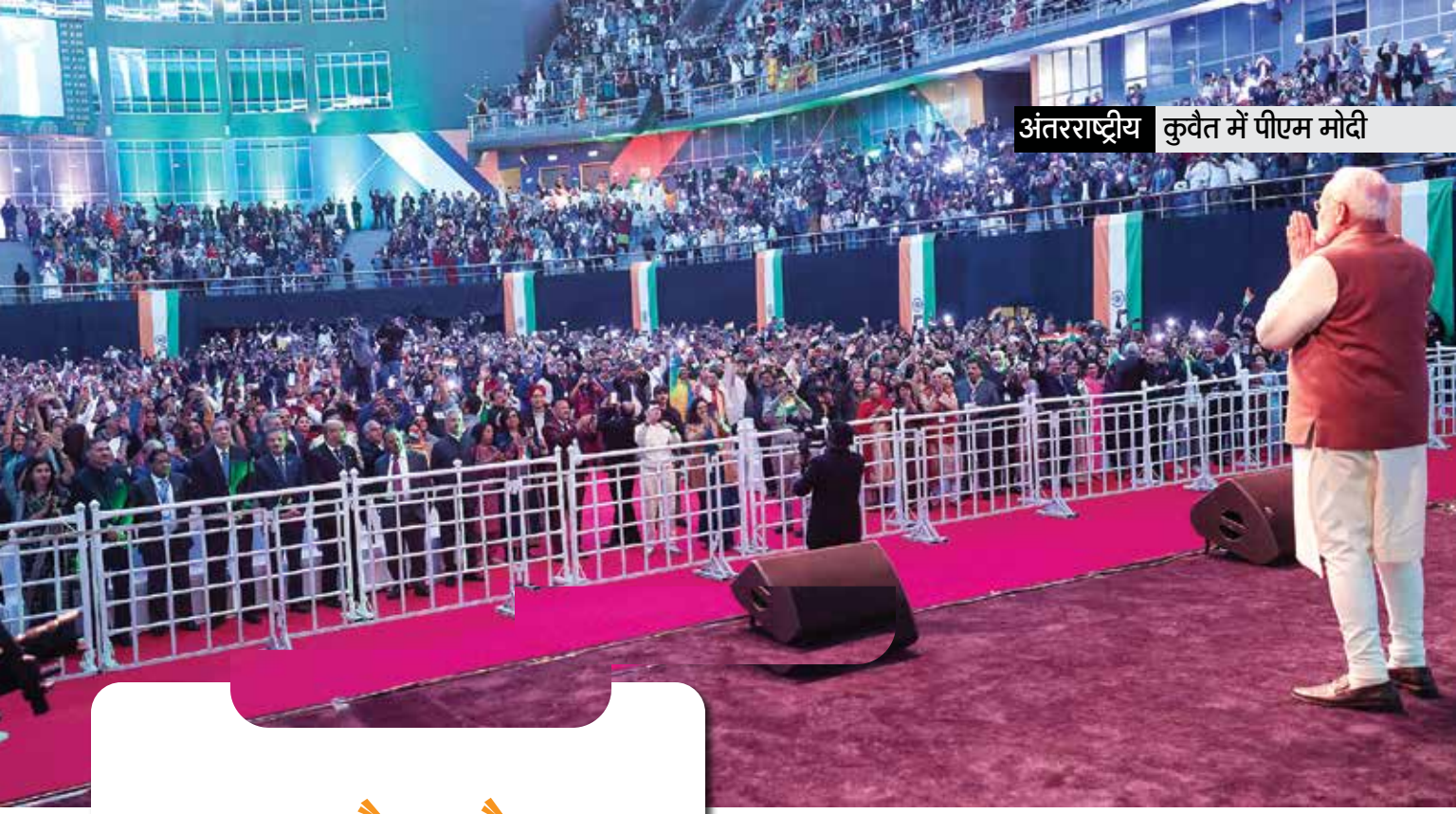
बढ़ा 5 वर्ष में

वर्ष	जेंडर बजट
2024-25	3,27,185
2023-24	2,38,220
2022-23	1,71,006
2021-22	1,53,326

आंकड़े करोड़ रुपये में

देशभर में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बालिकाओं को महत्व देने वाले एक सकारात्मक वातावरण के निर्माण में पूरे राष्ट्र को शामिल करना है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना ने राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के उद्देश्य को मजबूती दी है। महज 100 करोड़ रुपये के शुरुआती वित्तपोषण के साथ शुरू हुई यह योजना उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों में प्रमुख रूप से केंद्रित है, जहां लैंगिक असमानताएं स्पष्ट हैं। हालांकि, योजना पश्चिम बंगाल को छोड़कर देशभर में चलाई जा रही है। भारत सरकार की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार दिख रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर 2014-15 के लिंगानुपात 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया है।

एनएफएचएस-5 के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6 प्रतिशत पहुंच गया है तो 10 वर्ष या उससे अधिक उम्र की शिक्षा प्राप्त लड़कियों में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ लागू होने के बाद 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। स्कूली शिक्षा में प्राथमिक से उच्चतर माध्यम कक्षाओं के लिए 2021-22 में लड़कियों का नामांकन 12.28 करोड़ रहा। हरियाणा में माध्यमिक स्तर पर स्कूल में बालिकाओं का नामांकन 2014 में 79.86 फीसदी था, जो 2021-22 में 93.24 फीसदी पहुंच गया है। यहां यह बताना भी जरूरी है कि 1876 में प्रथम राष्ट्रीय जनगणना के बाद से पहली बार प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या अधिक हुई। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (वर्ष 2019-21) में प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,020 महिलाएं रजिस्टर हुईं हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 में 20-24 वर्ष की 47 फीसदी महिलाओं ने बताया कि उनकी शादी 18 वर्ष से कम आयु में हुई थी जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के बाद हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 में घटकर करीब आधी रह गई है। ●



भारत और कुवैत...

रिश्तों को नई उड़ान

भारत और कुवैत पारस्परिक सहयोग और सौहार्द भरे रिश्तों की मिसाल कहे जाते हैं। दोनों देशों के गहरे रिश्तों और आपसी विश्वास का प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि जहां 1961 तक कुवैत में भारतीय रुपया कानूनी मुद्रा के रूप में प्रचलित था तो वहीं भारत वह पहला देश है जिसने कुवैत को मान्यता दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिवसीय दौरे ने इन रिश्तों को एक नई उड़ान दी...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 दिसंबर को जब अमीर शेख मेशल अल-अहमद अल-जाबिर अल-सबाह के निमंत्रण पर कुवैत पहुंचे तो यह 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। मध्य पूर्व के किसी भी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह 14वां दौरा था। पीएम मोदी इससे पहले सात बार संयुक्त अरब अमीरात, दो-दो बार कतर और सऊदी अरब व एक-एक बार ओमान और बहरीन जा चुके हैं।

भारत और कुवैत के बीच सहयोग को बढ़ते आपसी व्यापार से भी समझा जा सकता है। 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक, भारत और कुवैत के बीच सालाना कारोबार करीब 10.47 अरब डॉलर का हुआ। यही नहीं, भारतीय निर्यात के आंकड़े में इस दौरान 34% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कुवैत, भारत का छठा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है। कुवैत ने भारत में करीब दस अरब डॉलर का निवेश भी किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिवसीय दौरे पर दोनों देश इन गहरे संबंधों को नया आयाम देने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण, तटीय रक्षा, समुद्री सुरक्षा, रक्षा उपकरणों के संयुक्त विकास और उत्पादन सहित द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर मिल कर काम करने पर राजी हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां 26वें अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में भी भाग लिया। पीएम मोदी और कुवैत राज्य के प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल-



कुवैत में दिखी मिनी भारत की झलक

कुवैत यात्रा के दौरान जब पीएम मोदी भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे तो वहां मिनी भारत की झलक दिखी। भारत के अलग-अलग राज्य और भारत की अलग-अलग बोली बोलने वाले लोग मौजूद थे लेकिन सबके दिल में भारत माता की जय की गूंज सुनाई दे रही थी।

पीएम मोदी ने कहा कि यह दिन निजी तौर पर मेरे लिए बेहद खास है। 43 वर्ष बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है। भारतीय समुदाय ने कुवैत के समाज में भारतीयता का तड़का लगाया है। कुवैत के कैनवास पर भारतीय हुनर का रंग भरा है। पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि आप लोगों ने कुवैत में भारत के टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का मसाला मिक्स किया है और इसलिए यहां सिर्फ आपसे मिलने ही नहीं आया हूं, आप सभी की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए आया हूं।

पीएम मोदी ने कहा कि जब भी वे कुवैत की लीडरशिप से बात करते हैं तो वो भारतीय समुदाय की प्रशंसा करते हैं। कुवैत के नागरिक भारतीयों की मेहनत, ईमानदारी कौशल क्षमताओं की वजह से उनका बहुत सम्मान करते हैं। भारत की वर्तमान सरकार ने कुवैत को सिर्फ डिप्लोमेसी से ही नहीं बल्कि दिलों को आपस में जोड़ा है। एक समय था जब कुवैत से मोती, खजूर और शानदार नस्ल के घोड़े भारत आते थे और भारत से बहुत सारा सामान कुवैत आता था। भारत के चावल, चाय, मसाले, कपड़े, लकड़ी कुवैत जाते थे। भारत की टीक वुड से बनी नौकाओं में सवार होकर कुवैत के नाविक लंबी यात्राएं करते थे। कुवैत के मोती भारत के लिए किसी हीरे से कम नहीं रहे हैं। आज भारत की ज्वेलरी की पूरी दुनिया में धूम है तो उसमें कुवैत के मोतियों का भी योगदान है।

अहमद अल-जबर अल-मुबारक अल-सबाह के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों पक्षों ने राजनीतिक, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, संस्कृति, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के आपसी संबंध सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक व व्यवस्थित सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य, जनशक्ति और हाइड्रोकार्बन पर मौजूदा संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) के अलावा व्यापार, निवेश, शिक्षा, कौशल विकास, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, सुरक्षा के साथ आतंकवाद-रोधी, कृषि व संस्कृति के क्षेत्रों में नए संयुक्त कार्य समूह भी स्थापित किए गए हैं।

दोनों देश की ओर से संयुक्त वक्तव्य में कुवैत की ओर से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में भारत द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत करने के साथ ही प्रौद्योगिकी, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य-सुरक्षा,

पीएम मोदी को कुवैत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार



कुवैत के अमीर शेख मेशल अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह ने पीएम मोदी को कुवैत के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, 'द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर' से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने इस पुरस्कार को भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती को, कुवैत में भारतीय समुदाय को और भारत के 140 करोड़ नागरिकों को समर्पित किया। इस पुरस्कार की शुरुआत 1974 में की गई थी और तब से चुनिंदा वैश्विक नेताओं को यह पुरस्कार दिया जा रहा है।

द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने वाले कदम

- दोनों देश ने सीमा पार आतंकवादी सहित आतंकवाद के वित्तपोषण नेटवर्क और सुरक्षित ठिकानों एवं आतंकी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का आह्वान किया।
- साइबर सुरक्षा में सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की, जिसमें आतंकवाद, कट्टरपंथ और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए साइबर स्पेस के उपयोग की रोकथाम शामिल है।
- भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का सदस्य बनने के कुवैत के फैसले का स्वागत किया, जो कार्बन के कम उत्सर्जन से जुड़े तरीकों को विकसित करने और सतत ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- वर्ष 2025 से 2029 तक के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सीईपी) का नवीनीकरण, दोनों पक्ष ने लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई।
- दोनों पक्ष ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर सहयोग करने तथा शैक्षिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म और डिजिटल पुस्तकालयों के अवसरों की खोज करने का निर्णय लिया। रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर भारत-कुवैत के बीच समझौता।
- युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार तथा युवा और खेल सार्वजनिक प्राधिकरण, कुवैत सरकार के बीच वर्ष 2025-2028 के लिए खेल के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और कुवैत के बीच सहमति।

लॉजिस्टिक्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों का पता लगाने में रुचि व्यक्त की गई।

पीएम मोदी की कुवैत के प्रधानमंत्री, क्राउन प्रिंस और अमीर से मुलाकातः पीएम मोदी की कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल-खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबा से मुलाकात हुई। दोनों नेता ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ समन्वय पर जोर दिया। पीएम मोदी की कुवैत के अमीर शेख मेशल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा से भी मुलाकात हुई। दोनों ने मजबूत ऐतिहासिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों को और आगे बढ़ाने एवं प्रगाढ़ करने के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता दोहराई। ●



साझा भविष्य के लिए साझेदारी को बढ़ावा

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायक की भारत यात्रा से श्रीलंका-भारत के बीच संबंधों में नई गति और ऊर्जा का सृजन हुआ है। दोनों देश ने पार्टनरशिप के लिए एक फ्यूचरिस्टिक विजन अपनाया है और आर्थिक साझेदारी में निवेश आधारित ग्रोथ एवं कनेक्टिविटी को प्रमुखता दी है। फिजिकल, डिजिटल और एनर्जी कनेक्टिविटी को भागीदारी के अहम स्तंभ के रूप में अपनाने का लिया है निर्णय...

भारत-श्रीलंका के लोगों का संबंध दोनों देश की सभ्यताओं से जुड़ा है। इसे इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब भारत में पाली भाषा को 'शास्त्रीय भाषा' का दर्जा दिया गया तो श्रीलंका में भी उसकी खुशी मनाई गई। संबंधों में मजबूती के लिहाज से फेरी सर्विस और चेन्नई-जाफना फ्लाइट कनेक्टिविटी की गई, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूती मिली।

श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नागपतिनाम और कन्केसंथूराई फेरी सर्विस की सफल शुरुआत के बाद, अब रामेश्वरम और तलाइमनार के बीच फेरी सर्विस शुरू की जाएगी। 'बौद्ध सर्किट' और श्रीलंका के 'रामायण ट्रेल' के माध्यम से पर्यटन की अपार संभावनाओं को साकार करने पर भी काम किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति दिसानायक को आश्वासन दिया है कि श्रीलंका के विकास के लिए उनके प्रयासों में, भारत एक भरोसेमंद और विश्वसनीय पार्टनर बना रहेगा। राष्ट्रपति के रूप में दिसानायक ने पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना, यह भी दोनों देश के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है।

भारत और श्रीलंका, दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष इस बात से सहमत हैं कि दोनों की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। ऐसे में रक्षा सहयोग समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने का निर्णय लिया और हाइड्रोग्राफी पर भी सहयोग की सहमति बनी। अपने वक्तव्य में



श्रीलंका के सभी 25 जिलों में भारत का सहयोग

- श्रीलंका को अब तक 5 अरब डॉलर का ऋण एवं अनुदान सहायता दी है।
- श्रीलंका के सभी 25 जिलों में भारत का सहयोग है। भारत प्रोजेक्ट्स का चयन पार्टनर देशों की विकास प्राथमिकताओं के आधार पर करता है।
- माहो-अनुराधापुरम रेल सेक्शन के सिग्नलिंग सिस्टम और कांकेसंथुराई बंदरगाह के पुनरुद्धार के लिए सहायता देने का निर्णय।
- अगले वर्ष से जाफना और पूर्वी प्रांत के विश्वविद्यालयों में 200 छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- अगले 5 वर्ष में श्रीलंका के 1,500 नौकरशाहों को भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- आवास, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचा के साथ-साथ श्रीलंका में कृषि, डेयरी और फिशरीज के विकास के लिए भी भारत सहयोग देगा।
- श्रीलंका में विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रोजेक्ट के लिए भी भारत भागीदारी करेगा।
- दोनों देश के बीच बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी और बहु-उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने पर काम किया जाएगा।
- श्रीलंका के पावर प्लांट्स के लिए **LNG** सप्लाई। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा के लिए दोनों पक्ष ने '**ETCA**' को जल्द संपन्न करने का निर्णय लिया।

पिछले कुछ वर्षों में द्विपक्षीय संबंध हुए हैं प्रगाढ़

दोनों नेताओं ने स्वीकार किया कि पिछले कुछ वर्षों में द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। इसका श्रीलंका के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पिछले दशक में राजनीतिक वार्ताओं में हुई वृद्धि और द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने में उनके योगदान को स्वीकार करते हुए राजनीतिक सहभागिता और तेज करने पर सहमति बनी।

श्रीलंका-भारत नौसैनिक अभ्यास-24

पूर्वी नौसेना कमान के तत्वावधान में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास एसएलआईएनईएक्स-24 (श्रीलंका-भारत नौसैनिक अभ्यास) 17 से 20 दिसंबर, 2024 तक विशाखापत्तनम में दो चरणों में आयोजित किया गया। 2005 में शुरू किया गया एसएलआईएनईएक्स द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों का महत्वपूर्ण संस्करण है जिसने पिछले कुछ वर्षों में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत किया है।

पीएम मोदी ने कहा कि कोलंबो सिक्युरिटी कॉन्क्लेव, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और विकास के लिए अहम प्लेटफॉर्म है। इसके अंतर्गत, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद निरोध, साइबर सुरक्षा, तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई, मानवीय सहायता और आपदा राहत जैसे विषयों पर सहयोग बढ़ाया जाएगा। दोनों देश ने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर मानवीय अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी ने आशा व्यक्त की है कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी और श्रीलंका के संविधान के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन और प्रांतीय परिषद चुनाव कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगी।

दोनों नेताओं ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि जिन विचारों पर सहमति बनी है उसके प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन से दोनों देश के बीच द्विपक्षीय संबंध गहरे होंगे। दोनों नेताओं ने अधिकारियों को उन विषयों पर कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिए जिन पर सहमति बनी है। द्विपक्षीय संबंधों को गुणात्मक रूप से बढ़ाने के लिए बातचीत जारी रखने का संकल्प लिया जो पारस्परिक रूप से लाभकारी हैं। ●



किसानों को समर्पित 2025 की मंत्रिमंडल की पहली बैठक

फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ा, डीएपी के लिए विशेष पैकेज

केंद्रीय मंत्रिमंडल की 2025 की पहली बैठक किसानों को समर्पित रही। इसमें दो प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, दोनों ही किसानों के कल्याण के लिए है। पहले फैसले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सफलता और 4 करोड़ से अधिक किसान के लाभ को ध्यान में रखकर आवंटन राशि बढ़ाई गई तो दूसरे निर्णय में डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर एकमुश्त विशेष पैकेज वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन फैसलों से जहां अन्नदाताओं को अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, वहीं किसानों को किफायती कीमतों पर डीएपी उपलब्ध कराने में भी मिलगी मदद...

निर्णय : वर्तमान में जारी केंद्रीय क्षेत्र की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सुविधाओं, प्रावधानों में संशोधन, समावेश तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी, आवंटन राशि बढ़ाई।

प्रभाव : 2021-22 से लेकर 2025-26 तक कुल 69,515.71 करोड़ रुपये के खर्च के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना साथ ही पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को भी 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से किसानों को फसल बीमा के तहत अधिक जोखिम सुरक्षा मिलेगी। योजना के कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल के लिए 824.77 करोड़ रुपये की निधि के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी फंड गठन की मंजूरी से प्रक्रिया भी आसान होगी। पॉलिसी के हिसाब से विश्व के सबसे बड़े और कुल प्रीमियम में तीसरी सबसे बड़ी बीमा योजना में 2023-24 में 4 करोड़ किसान को बीमा कवर मिला है। पिछले 8 वर्ष में किसानों को 1.70 लाख करोड़ रुपये के क्लेम का भुगतान किया गया है।

निर्णय : किसानों को डीएपी की किफायती दरों पर निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए 1 जनवरी 2025 से अगले आदेश तक एनबीएस सब्सिडी के अलावा एकमुश्त 3850 करोड़ रु. का विशेष पैकेज।

प्रभाव : किसानों को रियायती, किफायती और उचित मूल्य पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भू-राजनीतिक कारणों से डीएपी की कीमत बढ़ गई है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार इसका भार किसानों पर नहीं डालना चाहती। मंत्रिमंडल के निर्णय से बढ़ी हुई कीमत का भार विशेष पैकेज के तहत केंद्र सरकार उठाएगी और किसानों को 50 किलोग्राम का डीएपी बैग 1,350 रुपये में मिलता रहेगा। किसानों के कल्याण को ध्यान में रखकर उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता देना जारी रखते हुए, सरकार ने डीएपी उर्वरक की कीमत में कोई बदलाव नहीं करते हुए किसानों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने 2014-24 तक उर्वरक सब्सिडी 11.9 लाख करोड़ रुपये की दी है जो 2004-14 के एक दशक में दी गई 5.5 लाख करोड़ रुपये से दोगुनी से भी अधिक है।



हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमें अपने सभी किसान बहनों और भाइयों पर गर्व है जो हमारे देश का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। 2025 की पहली कैबिनेट हमारे किसानों की समृद्धि बढ़ाने के लिए समर्पित है। मुझे खुशी है कि इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



Narendra Modi
@narendramodi

केन-बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना से बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने वाली है। आज मध्य प्रदेश के खजुराहो में कई विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।



रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India
@DefenceMinIndia

हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक, भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाया जाए। इस लक्ष्य की प्राप्ति में, सेना की भूमिका बेहद अहम है। आप केवल सीमाओं के रक्षक ही नहीं हैं, बल्कि आप इस राष्ट्र के निर्माण के अग्रदूत भी हैं: रक्षा मंत्री



Amit Shah
@AmitShah

आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर अटल जी के नदियों को जोड़ने के विजन को साकार करते हुए मोदी जी ने खजुराहो में 'केन-बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना' की आधारशिला रखी।

इस परियोजना से बुंदेलखंड में सूखे की समस्या के समाधान के साथ-साथ कृषि, हरित ऊर्जा और रोजगार में वृद्धि होगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।



Nitin Gadkari
@nitin_gadkari

राष्ट्रीय रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र सरकार के विभागों एवं संगठनों में नवनियुक्त लगभग 71,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नागपुर के सीआरपीएफ ऑफिस, हिंगना रोड में इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर सब के साथ प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुना और नवनियुक्त भर्तियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरित किए।



Kiren Rijiju
@KirenRijiju

भारत की creative talent को दुनिया के सामने रखने का एक बहुत बड़ा अवसर आ रहा है। अगले साल हमारे देश में पहली बार World Audio Visual Entertainment Summit यानि WAVES summit का आयोजन होने वाला है: माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी

#MannKiBaat



Gajendra Singh Shekhawat
@gssjodhpur

भारत की creative talent को दुनिया के सामने रखने का एक बहुत बड़ा अवसर आ रहा है। अगले साल हमारे देश में पहली बार World Audio Visual Entertainment Summit यानि WAVES summit का आयोजन होने वाला है।

मोदी ने कहा, महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश

'मन की बात' कार्यक्रम में किया जिक्र



मनमोहन सिंह सबके प्रेरणास्रोत: मोदी

■ पूर्व प्रधानमंत्री के घर पहुंचकर मोदी ने दी श्रद्धांजलि ■ निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार आज होगा



प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस समारोह में बच्चों की प्रतिभा और बहादुरी को सराहा

देश के युवा विरासत से प्रेरणा लें



यूपी-मध्य प्रदेश के लाखों लोगों को केन-बेतवा जुड़ने से फायदा होगा

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा, परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर बदल देगी



गुकेश का आत्मविश्वास प्रेरणादायक : पीएम मोदी

शतरंज विश्व चैंपियन बनने के बाद भारतीय खिलाड़ी ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात



पीएम इंटर्नशिप योजना 1.27 लाख अवसर 6.21 लाख आवेदन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 1.27 लाख अवसरों के लिए करीब 6.21 लाख आवेदन मिले हैं। रविवार को सरकार ने यह जानकारी देते हुए कहा कि चयन की प्रक्रिया चल रही है। इस साल के आम बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य पांच वर्षों के दौरान शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप मुहैया कराना है।

योजना का लक्ष्य 2024-25 के दौरान 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान कराना है। इसके लिए सरकार ने एक

50 हजार गांवों के 58 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड का वितरण कल

नमन उनको जिनके लिए **राष्ट्रवाद** मानव जाति के सर्वोच्च आदर्श, **सत्यम, शिवम**, और **सुंदरम** से प्रेरित था, जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद की रचनात्मक शक्तियों को जगाया था जो सदियों से हमारे लोगों में निष्क्रिय पड़ी थी।

आजानुबाहु ऊंची करके
वे बोले, रक्त मुझे देना।
इसके बदले भारत की
आजादी तुम मुझसे लेना॥

– गोपाल प्रसाद व्यास



नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती (23 जनवरी)

पराक्रम दिवस



पराक्रम दिवस पर भारत के लोगों को शुभकामनाएं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम उनके जीवन और साहस का सम्मान करते हैं। हमारे देश की आजादी के प्रति उनका अटूट समर्पण प्रेरणा देता रहता है।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

न्यू इंडिया समाचार
पाक्षिक

आर.एन.आई, DELHIN/2020/78812, 16-31 जनवरी, 2025

आरएनआई DELHIN/2020/78812, दिल्ली पोस्टल लाइसेंस नंबर- DL (S)-1/3550/2023-25 डब्ल्यूपीपी संख्या- U (S)-98/2023-25, posting at BPC, Market Road, New Delhi - 110001 on 13-17 advance Fortnightly (प्रकाशन तिथि- 3 जनवरी 2025, कुल पृष्ठ-56)

प्रधान संपादक:
धीरेन्द्र ओझा, प्रधान महानिदेशक,
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक और मुद्रक:
योगेश कुमार बवेजा,
महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो

कमरा संख्या-278, केंद्रीय संचार ब्यूरो,
सूचना भवन, द्वितीय तल,
नई दिल्ली- 110003 से प्रकाशित

मुद्रण: जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा. लि.,
बी-278, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1,
नई दिल्ली-110020